ग्रीन रिवोल्ट

हरित-नीरा रहे वसुंधरा

पेजः 4
किसानों का पुराना दोस्त चमगादड़ अब शत्रु क्यों ?

रविवारीय, 10 - 16 मई 2020 वर्ष- एक, अंक-40, रांची, कुल पृष्ठ 4 हिन्दी साप्ताहिक R.N.I. No. JHAHIN/2019/78094 www.greenrevolt.news मूल्यः 2 रूपये

ग्रीन रिवोल्ट के पाठकों से आग्रह है कि आप पर्यावरण, कृषि, जल संरक्षण, पशुपालन, बागवानी , पेट्स, वृक्षारोपण से संबंधित खबरें, समस्यायें, लेख,सुझाव, प्रतिक्रियायें या तस्वीरें हमें अवश्य भेजें। हमारा इमेल एवं हवाट्सएप नंबर है।

greenrevolt2019@gmail.com

9798166006

संघर्ष में मां राह दिखाती है :हेमंत सोरेन

रांची : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने मातृ दिवस (मदर्स डे) के अवसर को राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने कहा संघर्ष में मां राह दिखाती है। अधिकारों के लिए लड़कर जीतना मां सिखाती है।

सभी को उनके घर अवश्य वापस लाया जाएगा : मुख्यमंत्री

रांची : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार प्रवासी झारखण्डवासियों को आश्वस्त करना चाहती है कि कुछ समय लगेगा लेकिन सभी को उनके घर अवश्य वापस लाया जाएगा। आपदा में सभी थोड़ा और धैर्य रखें। झारखण्ड सरकार अन्य राज्यों से बात कर अधिक संख्या में ट्रेनों के परिचालन को प्रयासरत है।

मरीजों की तेजी से बढ़ती संख्या, वैक्सिन और दवा दूर की कौड़ी और मजबूरन लॉकडाउन में छूट यानि अब

सीखें, कोरोना संग जीना

मुख्य संवाददाता

अब जबकि देश में मरीजों की संख्या सत्तर हजार के करीब पहुंचने को है और इस पर फिलहाल नियंत्रण की कोई उम्मीद भी नहीं दिखती। एम्स के निदेशक का ये बयान कि जून जुलाई में कोरोना संक्रमण देश में अपने उफान पर होगा और संक्रमितों की संख्या चार लाख तक पहुंच जायेगी जता गया कि भारत में कोरोना ने लाख प्रतिरोधों के बावजूद अच्छे से पांव पसार लिया है। इन सब के बीच लॉकडाउन में सरकार का कुछ छूट देना यही जता रहा है कि अब हमें कोरोना के साथ ही सतर्कता से काम करना है।

सरकार से लेकर आम आदमी को इस बात का अहसास है कि कोरोना के फैलाव पर अगर नियंत्रण नहीं हुआ तो भी लंबे समय तक ये लॉकडाउन जारी नहीं रखा जा सकता। अंततः उद्योग धंधों से लेकर ट्रांसपोर्ट और अन्य जरूरी चीजों को खोलना ही होगा। इसी कड़ी में सरकार ने दिल्ली से 15 शहरों के लिये ट्रेन सेवायें चालू भी कर दी हैं। अब कोरोना पर नियंत्रण हो या न हो धीरे-धीरे अन्य सेवायें भी चालू होंगी ही। स्पष्ट संदेश है कि खतरा टला नहीं है ,पर लॉकडाउन में सब कुछ ध्वस्त करने से बेहतर है सावधानी से अर्थव्यवस्था को चालू करना। जब तक इसकी कोई दवा और वैक्सिन नहीं बनती तब तक लोगों को इसके साथ ही जीना सीखना होगा। मास्क, सैनिटाइजर, लोगों से कम मिलना जुलना, बाजार दूकान आफिस में दूरी बनाये रखना अपनी आदत बनानी होगी। अब पहले की तरह उनमुक्तता लोग कुछ दिन भूल हीं जायें तो अच्छा।

केंद्र और राज्य सरकारों की बेरूखी

मुंबई से एक व्यक्ति अपनी पत्नी और चार साल के बेटे को लेकर पैदल ही हजारो किमी उत्तर प्रदेश के अपने गांव को चल पड़ता है, और रास्ते में ही उस शख्स की भूख और कमजोरी से मौत हो जाती है। उसकी पत्नी अनजान से गांव में पति के शव के पास बैठी रो रही है और बच्चा अपनी मां को चुप करा रहा है। संक्रमण के भय से गांव का कोई व्यक्ति उनके पास आने से डरता है। महिला के पास पैसे तो दूर खाने को भी कुछ नहीं है। पुलिस को खबर करने के बाद भी वह घंटो बाद पहुंचती है। उस महिला का सब कुछ लुट चुका है। महाराष्ट्र से अपने गांव को पैदल चले 16 मजदूर थक कर रेलवे ट्रैक पर ही सो जाते हैं और ट्रेन से कट कर उनकी मौत हो जाती है। दर्जनो ऐसे वाकये हुये हैं जिसमें पैदल ही अपने गांव को चले लोग हाइवे पर दुर्घटनाओं में मारे गये। ये सभी हृदयविदारक घटनायें हैं जिन्हें सरकार चाहती तो आसानी से रोक सकती थी। लेकिन लॉकडाउन में सरकारों का स्याह चेहरा नजर आया।

लॉकडाउन में सब कुछ बंद करके मजदूरों को जहां हैं वहीं कैद तो कर दिया गया, पर रोज कमाने खाने वाले करोड़ो मजदूरों के भोजन का इंतजाम सरकारें नहीं कर सकीं। उल्टे उन्हें घर भेजने के नाम पर उनसे भाड़े से ज्यादा पैसे वसूला गया। राजस्व के लिये शराब की दूकानें खुलीं पर इन्हें घर नहीं जाने दिया गया। इसमें केंद्र से लेकर तकरीबन सभी सरकारें लिप्त रही हैं। इससे बेहतर होता कि सरकार लॉकडाउन से पहले ही या लॉकडाउन एक के बाद ही इन मजदूरों को घर जाने देती। मजदूर अपने गांव में नमक रोटी खाकर भी सुरक्षित रह लेता। आखिर इन करोड़ो मजदूरों को लॉकडाउन में लंबे समय तक रोक कर भी संक्रमण रोकने में सरकार विफल रही और अब जब इन्हें गांव भेजा जा रहा है तो ये अपने घर संक्रमण लेकर पहुंच रहे हैं।

डॉक्टर, पुलिस, सेना भी चपेट में

सेना, पुलिस और अर्द्धसैनिक बल के जवान भी बड़ी संख्या में संक्रमित हुये हैं। बिहार में बीएमपी के कई जवान संक्रमित हो गये और पटना में पूरे परिसर को सील कर दिया गया। दिल्ली में एक पुलिसकर्मी संक्रमित था उसमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं दिख रहे थे लेकिन एकाएक उसकी तबियत खराब हुई और अस्पताल में उसकी दुखद मौत हो गयी। इस वाकये के बाद जब व्यापक पैमाने पर पुलिस, बीएसएफ, सीआरपीएफ के जवानों की जांच की गयी तो सैकड़ो जवान इससे संक्रमित पाये गये। यही हाल डॉक्टरों , नर्सों और अन्य चिकित्साकर्मियों का भी हुआ है। कई अस्पतालों में तो पीपीई किट जैसी बुनियादी चीज के अभाव में डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ संक्रमित हो गये।

राहत की बात

भारत में संक्रमण से मरने वालों की संख्या आज भी बहुत कम है। संभव है अगले सप्ताह तक देश में कोरोना मरीजों की संख्या एक लाख पार कर जाये। हर रोज तीन से चार हजार मरीजों की संख्या बढ़ रही है और मुंबई, गुजरात, दिल्ली जैसे राज्यों में तो मरीजों की संख्या तेजी से लगातार बढती ही जा रही है। लेकिन इन सबके बीच ये तथ्य भी निकल कर आ रहा है कि भारत में कोरोना से मौतों का आंकड़ा अभी भी ढाई हजार से कम है। ज्यादतर मरीज देर सबेर ठिक हो रहे हैं।

वहीं अमेरिका में तकरीबन अस्सी हजार मौतें हो चुकी हैं, ब्रिटेन, स्पेन, इटली तो इससे पहले से ही तबाह हैं। रूस जर्मनी जैसे देश भी लाख कोशिशों के बावजूद संक्रमण से होने वाली बेतहाशा मौतों पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं।

रांची- नई दिल्ली राजधानी सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन सप्ताह में दो दिन चलेगी

रांची : केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में लोगों की परेशानियों को देखते हुये दिल्ली से देश के मुख्य शहरों के लिये ट्रेनों का परिचालन शुरू किया है।

● ट्रेन संख्या 02454/02453 ट्रेन संख्या 02454 नई दिल्ली – रांची राजधानी सुपरफास्ट स्पेशल दिनांक 13 .05 .2020 को नई दिल्ली से रांची के लिए तथा ट्रेन संख्या 02453 रांची – नई दिल्ली राजधानी सुपरफास्ट स्पेशल दिनांक 14 .05 .2020 को रांची से नई दिल्ली के लिए खुलेगी ।

रेल मंत्रालय ने यह सुनिश्चित किया गया है कि दिनांक 12 मई 2020 से देश के विभिन्न शहरों के लिए नई दिल्ली से कुल 15 जोड़ी ट्रेनें चलेंगी इसी के अंतर्गत दिल्ली से रांची एवं रांची से दिल्ली के लिए भी निम्न समय के अनुसार सप्ताह में दो दिन राजधानी सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलेगी ।

● ट्रेन संख्या 02454/02453 नई दिल्ली रांची– नई दिल्ली राजधानी सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन निम्न समय के अनुसार चलेगी।

ट्रेन संख्या 02454 नई दिल्ली – रांची राजधानी सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन नई दिल्ली से बुधवार और शनिवार को 15 :30 बजे प्रस्थान करेगी, कानपुर आगमन 20 :25 बजे तथा प्रस्थान 20 :30 बजे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। आगमन 00 :45 बजे तथा प्रस्थान 00 :55 बजे एवं रांची आगमन 10 :00 बजे होगा

● ट्रेन संख्या 02453 रांची – नई दिल्ली राजधानी सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन रांची से प्रत्येक गुरुवार एवं रविवार को 17 :40 बजे प्रस्थान करेगी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन आगमन 01 :40 बजे तथा प्रस्थान 01 :50 बजे, कानपुर आगमन 05 :45 बजे तथा प्रस्थान 05 :50 बजे और नई दिल्ली आगमन 10 :55 बजे होगा।

उपरोक्त ट्रेन में कुल 20 कोच होंगे जिसमें एसी फर्स्ट क्लास के 01 कोच, एसी टू टियर के 05 कोच, एसी थ्री टियर के 11 कोच, 01 पैंट्री कार तथा 02 जनरेटर यान होंगे यह ट्रेन पूर्णता वातानुकूलित है। दिनांक 12 मई 2020 से जो 15 जोड़ी ट्रेनें चलेंगी उनके टिकेटिंग तथा अन्य जानकारी इस प्रकार हैं।

- श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के अलावा यह 15 जोड़ी ट्रेनें चलेंगी।
- यह ट्रेनें पूर्णतः वातानुकूलित होंगी ।
- इन ट्रेनों के लिए आईआरसीटीसी की वेबसाइट से ही ई टिकटिंग प्रणाली से टिकट प्राप्त किए जा सकेंगे।
- इन टिकटों के खरीदने के लिए अग्रिम अवधि अधिकतम 7 दिनों की है।
- यात्रियों को स्वयं का खाने पीने का सामान साथ रखना होगा
- यात्रियों को स्टेशन पर कम से कम 90 मिनट पहले पहुंचना होगा ताकि उनका समय पर थर्मल स्क्रीनिंग किया जा सके।
- ट्रेन में किसी भी प्रकार का चादर, कंबल या पर्दे नहीं दिए जाएंगे, यात्री अपने साथ स्वयं उपयोग के लिए चादर एवं कंबल लेकर जायें।
- यात्रियों के पास स्टेशन पर आने एवं स्टेशन से जाने के लिए कंफर्म ई टिकट होना आवश्यक है
- अगले आदेश तक अन्य मेल एक्सप्रेस पैसेंजर एवं सब अर्बन ट्रेनें रद्द रहेंगी ।

पेज तीन भी देखे .....

अन्नदाता किसानों के मनोबल को बनाये रखने के पहल की जरूरत

संवाददाता

रांची : झारखण्ड में सब्जियों का सरप्लस उत्पादन होता है। सब्जी की खेती पर छोटे, मझोले एवं बड़े किसानों की आजीविका काफी हद तक निर्भर करती ह। पिछले 4-5 महीनों से हो रही बारिश से किसानों को फायदा कम और नुकसान काफी हुआ ह। कोरोना संकट की वजह से लॉक डाउन लागु होने पर किसानों को कृषि कार्य के लिए रियायत तो मिली. लेकिन स्थानीय बाजार में काफी सस्ती दर व खरीददार की कमी और बाहरी व्यापारी व्यापारी के नहीं आने से किसानों को काफी आर्थिक क्षति उढानी पड़ी ह। बेमौसम बारिश व कोरोना संकट की मार से किसान हताश ह। पूँजी के आभाव में आगे की खेती मामले में संशय में है।

नगडी प्रखंड के देवरी गाँव के किसान किशोर साहु ने करीब 3.2 एकड़ में 90 हजार की लागत से बंधा गोभी, फ्रेंच बीन और मटर की खेती की. बारिश से बंधा गोभी फसल गल गई, अधिकतर फ्रेंच बीन पौध को नुकसान और मटर को फल लगने समय भारी क्षति हुई। किशोर साहु

बताते है कि उन्हें 24 हजार मात्र आमदनी हुई और करीब 2.50 लाख का नुकसान हुआ है। बर्बाद फसल को गाय को खिलाया और बाजार नहीं होने से लाचार होकर बचे फसल वाले खेत की जुताई करना पड़ा. अभी 50 - 50 डेसीमल जमीन में फुल गोभी और गरमा मकई लगाया है। लगातार बारिश से मकई फसल पर कीड़े का काफी प्रकोप है और दवा देने के बावजूद कीड़े का नियंत्रण नहीं हो रहा है। गाँव के सब्जी उत्पादक 20 किसानों का भी यही हालात है। खेतों की जुताई कर

अदरख, गांधारी और पालक साग की खेती की शुरूआत किसानों ने की है। नगडी प्रखंड के पिस्का नगडी गाँव के किसान बजरंग साहु ने करीब 1.2 एकड़ में 45 हजार की लागत से फूल गोभी, बंधा गोभी और करैला की खेती की लगातार बारिश से करैला फसल को काफी क्षति हुई फूल गोभी व बंधा गोभी की अच्छी फसल हुई, लेकिन बाजार में खरीददार नहीं होने से पशु को खिलाना पड़ा। अभी करीब एक एकड़ में हरी मिर्च और 40 डेसीमल में अदरख की खेती शुरू की है। गाँव के अन्य 10 सब्जी

उत्पादक किसानों ने ईख, अदरख एवं गरमा मकई की खेती की ह। बारिश से मकई फसल में कीड़ो का प्रकोप काफी ज्यादा हो जा रहा है।

कुडलाटोली गाँव के किसान राजेन्द्र महतो ने 1.2 एकड़ दौन भूमि में बंधा गोभी, फ्रेंच बीन (मोटा व पतला), गाजर, मटर एवं गरमा मूली की खेती में करीब 65 हजार पूँजी का निवेश किया। बारिश से सब्जी फसलों को कुछ क्षति हुई। लेकिन लॉक डाउन में बाजार के आभाव में सब्जियों की बिक्री नहीं होने से 18 हजार मात्र ही आमदनी हुआ। अभी उनके 60 डेसीमल खेतों में भिन्डी, फूल गोभी, टमाटर एवं मूली लगा ह। राजेन्द्र महतो कहते है कि 15 दिनों में सब्जी फसल तैयार हो जायेगी। लेकिन लॉक डाउन में बाजार का आभाव और लगातार वर्षा ने चिंता बढा दी है। अब नुकसान होने से आगे खेती के कार्य को पूँजी के बिना जारी रखना असंभव दीखता है।

नगडी प्रखंड के कुडलाटोली गाँव के किसान प्रमोद महतो ने बताया कि करीब एक एकड़ में 21 हजार की लागत से .. *पेज तीन पर जारी .....*

राज्य में अफ्रीकन स्वाइन फीवर ने सूकरों में दी दस्तक

रांची :अफ्रीकन स्वाइन फीवर विषाणु संक्रमण ने सूकर में दी दस्तक विशेषज्ञों ने प्रदेश में संक्रमण से बचाव के सुझाव दिए सूकर आबादी के मामले में देश में झारखण्ड का दूसरा स्थान है पशु गणना, 2019 के अनुसार प्रदेश में सूकर की करीब 12.80 आबादी है। बीएयू के वैज्ञानिकों ने बाहर के व्यापारियों को सूकर बेचने पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गयी है। उत्तर-पूर्वी राज्यों से सूकरों एवं उत्पादों के आवागमन पर रोक लगाने की सलाह दी गयी है।

संकटकाल में देश सेवा में लगे हुये हैं सीसीएल कर्मी - सीएमडी सीसीएल

संवाददाता रांची : कोरोना वायरस से उत्पन्न इस वैश्विक महामारी के दौरान घोषित लॉकडाउन में जहां पूरा देश एक साथ खड़ा है, वहीं सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) अपने कर्तव्यों का पूरी संवदेनशीलता, सजगता और समर्पण

कोविड-19 से संक्रमित कुल 12 मरीज सीसीएल गांधीनगर,अस्पताल में भर्ती

के भाव से निर्वहन कर रहा है । वर्तमान (07 मई तक) में सीसीएल के केन्द्रीय अस्पताल गांधीनगर में कोविड-19 से ग्रसित कुल 12 मरीजों का ईलाज किया जा रहा है। डेढ़ वर्षीय बच्चे सहित एक दंपति को रिम्स, रांची रेफर किया गया है। नियमानुसार मरीजों का कोरोना जांच के लिए राज्य प्रशासन द्वारा पुनः सैंपल लिया गया है। यह जानकारी गांधीनगर के मुख्य चिकित्सा सेवा (प्रभारी) डॉ मंजु मिश्रा ने दी है।

सीसीएल ने डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य को सुरक्षित रखने के लिए लगभग 3100 पीपीई की खरीदी की है। प्रबंधन द्वारा चार (4) पोर्टेबल वेंटीलेटर वेंटिलेटर खरीद की प्रक्रिया जारी है। सीएमडी, सीसीएल गोपाल सिंह ने सभी कोरोना वारियर्स को उनके श्रेष्ठ और लगातार कार्य करने के लिए प्रेरित किया और कहा कि सीसीएल कर्मी इस विपरित परिस्थिति में भी देश सेवा में सतत कार्य कर रहे हैं। ज्ञात हो कि पूर्व में उपायुक्त महिमापत रे एवं एस एस पी, रांची अनीश गुप्ता ने गांधीनगर स्थित सीसीएल, गांधीनगर केंद्रीय अस्पताल का निरिक्षण किया था, जिसे कोविद-19 अस्पताल बनाया गया है। उन्होने सभी चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ को अपनी मेडिकल सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया था।

गांधीनगर अस्पताल सहित सीसीएल के अन्य तीन केंद्रीय अस्पताल, झारखंड के कोरोना संक्रमित से सम्बंधित मामलों से निपटने के लिए तैयार हैं। सीसीएल के कोविड-19 चार केन्द्रीय अस्पतालों में ऑक्सीजन सपोर्ट बेड, लाइफ सपोर्ट के साथ एम्बुलेंस, चौबीसों घंटे पर्याप्त ऑक्सीजन सपोर्ट एवं अन्य सुविधायें सुनिश्चित की गयी हैं ताकि कोरोना वारियर्स किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहें ।

सरकार और सभी स्टेकहोल्डर्स के सहयोग से, सीसीएल, अपने अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक गोपाल सिंह के कुशल नेतृत्व में कोविद -19 से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए चिकित्सा सेवाओं के साथ साथ विभिन्न माध्यम से जन सेवा कर रहा है । देश में कोरोना का प्रकोप बढ़ते ही सीसीएल की चिकित्सीय टीम सीएमडी श्री गोपाल सिंह की पहल पर अपनी तैयारियां मार्च माह से ही प्रारंभ कर दी थी।

भारत में अभी बाकी है कोरोना का चरम

राजेश कुमार

हर किसी के मन में यही सवाल है, आखिर कब तक महामारी का यह रूप देखने को मिलेगा? इसके चलते तरह-तरह की अफवाहें भी सोशल मीडिया पर हैं, लेकिन विशेषज्ञों की मानें तो दुनिया के महामारी प्रभावित पांच देश कोरोना का शीर्ष देख चुके हैं, भारत को अभी थोड़ा वक्त इंतजार करना पड़ सकता है क्योंकि जांच में तेजी देरी से आई।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया का कहना है, सिर्फ आंकड़ों को देख पूरे देश का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अभी कर्व ग्राफ बढ़ रहा है। जबकि कुछ देशों में यह नीचे आ चुका है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार, कुछ देशों में वायरस का कर्व ग्राफ नीचे जा रहा है जिसमें अमेरिका भी शामिल है। एक सप्ताह की स्थिति पर तैयार रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका, इटली, स्पेन, बेल्जियम और नीदरलैंड में कर्व नीचे की ओर आने लगा है। हालांकि ईरान, जर्मनी, ब्राजील, फ्रांस, यूके और भारत में अभी यह ऊपर की ओर है।डॉ. गुलेरिया बताते हैं, देश में डबलिंग व

8 दिन में 22 हजार से ज्यादा मरीज

दिन	केस	मौत	डिस्चॉर्ज
1 मई	1755	77	692
2 मई	2411	71	953
3 मई	2487	83	869
4 मई	2573	83	875
5 मई	3875	194	1399
6 मई	2680	111	1022
7 मई	3561	89	1084
8 मई	3390	103	1273
कुल	22,732	811	8167

संक्रमण दर काफी हद तक नियंत्रण में दिखाई देगी। अभी रोजाना करीब 80 हजार जांच हो रही हैं। कुछ दिन में यह एक लाख से ज्यादा भी होंगी। तब हो सकता है कि रोज आ रहा आंकड़ा और भी ज्यादा हो।

कुल संक्रमितों की संख्या साठ हजार पार हो चुकी है। डबलिंग रेट (दोगुना दर) की बात करें तो 26 अप्रैल को संक्रमित मरीजों की संख्या 25 हजार पार हो गई थी। इसके ठीक 12वें दिन 7 मई को यह संख्या दोगुना यानी 50 हजार पार हुई। इसी तरह, बीते 24 घंटे में 80,375 सैंपल की जांच हुई है, जिसमें से 3390 सैंपल पॉजिटिव मिले यानी 4.21 फीसदी। इसे संक्रमण दर मानते हुए विशेषज्ञों का कहना है, यह आंकड़ा लंबे समय से एक समान बना हुआ है जिससे साबित होता है कि देश में संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में हैं।

हर दिन बढ़ रहे मरीजः क्या है संक्रमण का कर्व :आईसीएमआर के महामारी विशेषज्ञ बताते हैं कि विज्ञान में महामारी के विकास को अलग नजरिए से देखा जाता है। महामारी का घुमावदार ग्राफ यानी कर्व होता है, जो एक वक्त तक ऊपर बढ़ता है, फिर यह तेजी से नीचे जाने लगता है। यह प्रक्रिया कोरोना संक्रमण में भी चल रही है। ज्यादातर देशों में यह कर्व नीचे बढ़ने लगा है लेकिन भारत में अभी यह ऊपर की ओर ही बढ़ रहा है। इसे नीचे की ओर घूमने में कम से कम दो से चार सप्ताह लग सकते हैं। इसीलिए विशेषज्ञ जून से जुलाई के बीच देश में कोरोना का शीर्ष आने की उम्मीद जता रहे हैं।

आंकड़े कम आना और ज्यादा भयावह

सफदरजंग अस्पताल के सामुदायिक मेडिसिन विभागाध्यक्ष डॉ. जुगल किशोर का कहना है, लोग आंकड़ों से डर रहे हैं, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। यह ऐसी प्रक्रिया है जिसे लोगों में पैनिक के चलते रोका नहीं जा सकता। जांच तेजी से हो रही है तो मरीज भी तेजी से सामने आ रहे हैं। अगर यह आंकड़े नहीं बढ़ेंगे तो महामारी को नहीं रोक पाएंगे।

हमसे भी हुई हैं कई भूल...

एक वैज्ञानिक बताते हैं कि ऐसा नहीं कि कोरोना को समझने में हमसे भूल नहीं हुई। जनता कर्फ्यू के बाद लॉकडाउन हुआ तो 3-4 दिन बाद तब्लीगी जमात की खबर मिल गई। फिर प्रवासी मजदूरों का पलायन, जो अभी भी चुनौती बना हुआ है। कंटेनमेंट जोन पर गहन अध्ययन के साथ राज्यों को जानकारी दी गई, पर कई जगहों से शिकायतें मिल रही थीं। रैपिड एंटीबॉडी जांच किट्स को लेकर एक सच यह भी है कि उससे जुड़े दिशा निर्देशों पर सही अमल भी नहीं हुआ, जिससे सर्विलांस में रुकावट भी आई है।

सबसे बड़ी वैक्सीन सामाजिक दूरी

लैब की संख्या बढ़ाना भी एक चुनौती थी जो 400 पार हो चुकी है। संभव है, अगले कुछ दिन में लॉकडाउन हटा लिया जाए, पर सामाजिक दूरी, मास्क व हाथ धोने की आदत डालनी ही होगी। दवा बनने से पहले इसे सबसे बड़ी वैक्सीन समझ लीजिए।

दीपक प्रकाश को देखने रिम्स पहुंचे मुख्यमंत्री

रांची : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान , रिम्स के सुपर स्पेशियलिटी विंग पहुंचकर यहां भर्ती भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश का हाल जाना और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की ' मुख्यमंत्री ने रिम्स के निदेशक डॉ डके सिंह और विशेषज्ञ चिकित्सकों से उनके इलाज से संबंधित जानकारी ली ' इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद भी मौजूद थे।

जनता सिर्फ राजस्व प्राप्ति का सामान है?

शराब से राजस्व कमाने की चिंता में सरकारें आपराधिक कृत्य तक करने लगी हैं। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने पहले दिन शराबियों की भयंकर तलब को आंक लिया और अगले ही दिन शराब की कीमतें 70 प्रतिशत बढा दी। ये हम सभी जानते हैं कि नशा करने वाला तो नशे के लिये घर के सामान तक बेच डालता है ऐसे में जरूरी चीजों पर पाबंदी जारी रख कर शराब बेचने का सरकारों का ये कृत्य किसी अपराध से कम नहीं है। राज्यों में पहले शराब के मुद्दे पर सरकारें गिरती और बनती रही हैं। आंध्र प्रदेश में एक सरकार के चुनाव हारने का प्रमुख कारण शराबबंदी से आक्रोशित जनता का खिलाफ होना था। वहीं कहा जाता है कि बिहार में महिलाओं ने शराबबंदी के वादे को देख कर ही वर्तमान सरकार को अपना समर्थन दिया। इसमें कोई दोराय नहीं कि जनता में शराब की ये चाहत भारत जैसे देश के लिये कोई सुखद चीज नहीं है। जितना राजस्व देश को शराब से आता है उससे ज्यादा खर्च देश भर में शराब के चलते पैदा होने वाली समस्याओं पर खर्च हो जाता है।

झारखंड में एक बार शराब से इतना ज्यादा राजस्व आने लगा कि संबंधित मंत्री ने खुद ये कह दिया कि हर महिने इससे आ रहे प्रचुर राजस्व से तो खुश हुआ जा सकता है, पर हमें ये भी सोंचना होगा कि झारखंडी समाज कहां जा रहा है?

शराबबंदी के वादे पर छत्तीसगढ में आयी भूपेश बघेल सरकार ने तो शराब की होम डिलिवरी का इंतजाम कर दिया और इसके लिये बकायदा एक मोबाइल एप भी लांच कर दिया जिसमें आप 15 किमी के दायरे में सबसे नजदीक के शराब दूकान का पता लगा कर उसे शराब आर्डर कर सकते हैं और आनलाइन सुरक्षित पेमेंट भी कर सकते हैं। इसके लिये बाइक वाले डिलिवरी ब्वॉय नियुक्त किये गये हैं जिन्हें पास दिया गया है। तो क्या ये माना जाये कि सरकारों की नजर में जनता सिर्फ राजस्व प्राप्त करने का एक सामान भर हैं?

> लाकडाउन में सख्ती से शिशुओं की मौत जन्म से पहले हो जा रही है, पर शराब की बिक्री जरुरी है।
>
> शराब से राजस्व का मोह बहुत कम सरकारें त्याग पाती हैं। बिहार और गुजरात जैसे गिने चुने राज्य ही इस लालच से बच पाये हैं। दिल्ली उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में तो लोगों ने इस कोरोना संकट में भी दो-दो किमी लंबी लाइनें लगा कर शराब की खरीददारी की और पहले ही दिन यहां 900 करोड़ की शराब बिकी। दिल्ली में तो लोगों ने तकरीबन दुगुनी कीमत की भी परवाह नहीं की। ये जनता और सरकार दोनों के लिये धिक्कार की बात है।
>
> बिहार ने शराब बंदी के कुछ साल बाद ये दावा पेश किया था कि हम शराब से जितना राजस्व प्राप्त करते थे उससे ज्यादा खर्च सरकार को शराब जनित बीमारियों के ईलाज, अपराध नियंत्रण, सामाजिक बुराइयों और इससें होने वाली दुर्घटनाओं पर हो रहा था।

अमेरिकी किसान फ्री में बांट रहे हैं आलू

अमेरिका के किसानों ने खाने की बर्बादी को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। वहां के किसानों अपने आलूको खेत में ही छोड़ दिया है या उसे फ्री में बांट रहे हैं। आलूलेने वाले लोगों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। कोरोना वायरस महामारी की वजह से किसानों के पास अपनी फसल बेचने के लिए कम ही विकल्प बचे हैं ऐसे में वो मुफ्त में लोगों को आलू बांट रहे हैं। एक किसान ने गुरुवार को पश्चिमी वाशिंगटन राज्य के एक मॉल के बाहर आलू से भरा ट्रक लगाया तो मुफ्त में आलू लेने के लिए कारों की लंबी लाइन लग गई। वाशिंगटन आलू कमिशन ने कहा कि लगभग एक अरब पाउंड आलू जिसे आमतौर पर फ्रेंच फ्राइज और हैश ब्राउन में इस्तेमाल किया जाता है, गोदामों में पड़ा है। ये गोदाम आमतौर पर जुलाई की फसल के आगे खाली हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि आलूको बांटने के सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। एक बार में 100,000 पाउंड आलू बांटने के लिए दिए जा रहे हैं। मार्केटिंग कमिशन के निदेशक ब्रांडी टकर ने कहा, वॉशिंगटन में हर किसी को अब से चार जुलाई तक लगभग 500 पाउंड आलू खाने होंगे।

वाशिंगटन के लगभग 90 फीसदी आलू को खाद्य सेवा में इस्तेमाल किया जाता है जोकि अंतरराष्ट्रीय बाजारों का लगभग आधा है। यूरोप में आलू उत्पादकों को भी भारी मात्रा में नुकसान का सामना करना पड़ा है। आयोग मई के अंत तक आलू दान करने के एक दर्जन से अधिक कार्यक्रमों की योजना बना रहा है। वाशिंगटन के किसान एडम वेबर का कहना है कि आलू को फेंकने से बेहतर है कि उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाए। उन्होंने कहा कि इस बार आलू की फसल पर भारी नुकसान हुआ है। प्रति टन आलू की कीमत 200 डॉलर से गिरकर 30 डॉलर तक रह गई है। अगली बार वो कम आलू की खेती करेंगे।

चीनी उद्योग अगले वर्ष भी देगा कड़वाहट

लॉकडाउन के दौरान देश में चीनी की कम खपत, एथेनॉल की घटती मांग और अंतरराष्ट्रीय शुगर बाजार में बदली परिस्थितियों के चलते मौजूदा समय के साथ-साथ अगले सीजन में भी चीनी मिलों के सामने नकदी का संकट बढ़ेगा, इसका सीधा असर भारत के करीब एक लाख करोड़ रुपये के चीनी उद्योग के साथ ही 5 करोड़ गन्ना किसानों पर भी पड़ेगा और आर्थिक संकट में फंस सकते हैं देश के 5 करोड़ गन्ना किसान

मनीष मिश्र

लॉकडाउन के दौरान नकदी संकट झेल रहीं चीनी मिलों और किसानों के लिए अगला साल भी मुश्किलें खड़ी करने वाला है। कम खपत के चलते चीनी मिलों को चीनी बेचने में दिक्कत आ रही है तो क्रूड ऑयल सस्ता होने से एथेनॉल की मांग भी घटी है। इन वजहों से चीनी मिलें नकदी संकट झेल रही हैं जो अगले साल और बढ़ने के आसार हैं। माना जा रहा है कि किसानों को गन्ना बेचने और भुगतान की समस्या भी खड़ी होगी।

भारत दुनिया में सबसे अधिक चीनी पैदा करता है, और खपत भी करता है, लेकिन लॉकडाउन से जो खपत होती थी, वह नहीं हो पा रही है। चीनी मिलों के पास स्टॉक बढ़ रहा है। अगले साल इसके और बढ़ने के आसार हैं। जाहिर है कि अगर चीनी नहीं बिकेगी तो किसानों के भुगतान में दिक्कत आएगी। भारत सरकार सरकार के अधीन कार्य करने वाले 'कृषि मूल्य एवं लागत आयोग' के अनुसार भारत में हर साल चीनी की खपत 275 लाख टन की है, जो कि कुल उत्पादन का करीब 65-70 प्रतिशत होती है। भारत का चीनी उद्योग करीब एक लाख करोड़ रुपये का है, आयोग के अनुसार वर्ष 2018 तक भारत में 732 चीनी मिलें स्थापित हैं, जिनमें 524 चालू हैं।

हालात बदलते ही किसानो को कराएंगे पूरा भुगतान

लॉकडाउन में हमारा चैलेंज था, कि गन्ने की पेराई करा दें, पूरे भारत को देखें तो यूपी अकेला ऐसा राज्य है जिसने अकेले 119 मिलें चलाईं. निंरतर गन्ने की पेराई हो रही है, छह मई तक के आंकड़ों के अनुसार हम पिछले साल की तुलना में इस साल चार करोड़ क्विंटल गन्ने की अधिक पेराई कर चुके हैं। किसानों का 55 प्रतिशत भुगतान हो चुका है, जैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं, हम गन्ना किसानों का भुगतान कराएंगे :

सुरेश राणा, कैबिनेट मंत्री, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास उत्तर प्रदेश

15 जून चक चलाई जाएंगी चीनी मिलें

इस दौरान हमारे सामने चीनी मिलें चलाने का संकट सबसे पहले था, हम गन्ने की पेराई कर रहे हैं, 15 जून तक चीनी मिलें चलेंगी। नकदी संकट के दौरान पूरी कोशिश होगी कि चीनी मिलें जितने की भी चीनी बेचें, उसका 85 प्रतिशत गन्ना किसानों को भगुतान अवश्य हो, बाकी से वे अपना खर्च चलाएं।

संजय आर भूसरेड्डी, गन्ना एवं चीनी आयुक्त

भारत में 30 अप्रैल, 2020 तक चीनी का उत्पादन

राज्य	उत्पादन (लाख टन)
यूपी	116.52
महाराष्ट्र	60
कर्नाटक	33.8
तमिलनाडु	5.41
गुजरात	9.02
अन्य राज्य	32.5

(स्त्रोत-भारतीय शुगर मिल संगठन)

चीनी की खपत घटी

उत्तर प्रदेश चीनी मिल संघ के महासचिव दीपक बुखारा कहते हैं, ये जो 70 प्रतिशत चीनी की खपत भारत में होती है। शीतल पेय बनाने वाली कंपनियां, आइसक्रीम, मिठाई की दुकानों, शादी समारोहों पर सबसे अधिक चीनी की खपत होती है। जो लॉकडाउन के कारण ठप है। इस समय सिर्फ घरों में सप्लाई हो रही है। चीनी मिलों का स्टॉक बढ़ रहा है, बिक्री न होने से नकदी का संकट भी पैदा हो रहा है। अगर एक्सपोर्ट और चीनी की खपत नहीं बढ़ी, तो आगे पूरे साल चीनी के मूल्य कम रहेंगे,और अगले सीजन में किसानों के भुगतान पर संकट गहरा सकता है।

चीनी स्टॉक बढ़ेगा तो होगा नकदी संकट

दीपक अगले सीजन के संभावित संकट को कुछ इस तरह समझाते हैं, 'चीनी मिलें पूरे साल चीनी बेच कर अपना खर्च चलाती हैं, और किसानों को भुगतान भी करती रहती हैं। अगर चीनी नहीं बिकेगी तो, अगले साल के स्टॉक में जुड़ जाएगी, और अगले गन्ने के सीजन की चीनी भी आ जाने से स्टॉक बढ़ेगा, तो अधिक चीनी खपानी होगी।

मिलों के सामने नकदी का संकट बढेगा

मुजफ्फरनगर के अमीनगर सराय निवासी गन्ना किसान रघुनंदन शर्मा भी इस खतरे को भांप रहे हैं। कहते हैं, इस साल अपना गन्ना जैसे-तैसे बेच लिया लेकिन उनके गांव में बहुत गन्ना खेतों में खड़ा है। अब अगर मिलों की चीनी नहीं बिकेगी तो समस्या अगले साल और बढ़नी ही है, जिसका सीधा असर हम किसानों पर पड़ेगा।

अंतरराष्ट्रीय चीनी उद्योग पर असर

आने वाला साल चीनी मिलों और किसानों के लिए दिक्कत वाला होगा इसे समझाते हुए सीतापुर जिले में स्थित एक चीनी मिल के अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा : दुनिया में क्रूड ऑयल की कीमतें कम चल रही हैं, ब्राजील में ऐथेनॉल की खपत कम होगी, तो वो चीनी बनाएगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक चीनी का एक्सपोर्ट ब्राजील ही करता है। मौजूदा समय में विश्व में कुल निर्यात का 44.7 प्रतिशत अकेले ब्राजील करता है, जबकि भारत की इसमें हिस्सेदारी महज 3.2 प्रतिशत ही है। अगर ब्राजील सस्ती कीमत पर चीनी निर्यात करेगा तो भारत के लिए निर्यात और मुश्किल होगा।

खपत कम होने से चीनी की कीमतें भी घटीं

लॉकडाउन का असर चीनी की कीमतों पर पड़ा है, उत्पादन की अपेक्षा खपत कम होने से कीमत 3300 रुपये प्रति क्विंटल से 3100 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गए हैं। नकदी संकट से जूझ रही चीनी मिलों को यूपी सरकार ने सहूलियत देते हुए आदेश दिया कि वह किसानों को सीधे चीनी दे सकती हैं, लेकिन यह प्रस्ताव भी किसानों को रास नहीं आया।

इस तरह बढ़ रहा है बकाया

'इस्मा' के महानिदेशक अविनाश शर्मा ने एक जानकारी देते हुए कहा कि मौजूदा हालात में चीनी मिलों पर किसानों का बकाया बढ़कर 18,000 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि बीते माह मार्च-अप्रैल में चीनी की बिक्री पिछले साल के मुकाबले 10 लाख टन कम हुई है।

विशाखापत्तनम गैस रिसाव:दोषी कौन ?

प्रभुनाथ शुक्ल

आंध्र प्रदेश के विशाखापट्नम में एलजी पॉलिमर्स कम्पनी में गैस रिसाव के चलते एक मासूम बच्चे समेत दर्जन भरलोगों की मौत हो चुकी है। कई मवेशी भी अपनी जान गंवा बैठे। तीन सौ से अधिक लोग अस्पताल इलाज के लिए भर्ती हैं। 80 से अधिक लोग जिंदगी और मौत के बीच वेंटीलेटर पर हैं। 1500 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। इस घटना ने 36 साल पुरानी भोपाल गैस त्रासदी की याद फिर एक बार ताजा कर दिया है। भोपाल में 03 दिसम्बर 1984 को अमेरिकी कम्पनी यूनियन कार्बाइट से जहरीली गैस लीक होने से 15 हजार से अधिक लोगों की मौत हुई थी और हजारों लोग साँस और दूसरी शारीरिक बीमारियों से ग्रसित हुए थे। काफी संख्या में लोग अंधे और विस्थापित हो गए थे। इतने सालों बाद भी पीड़ितों को आज तक न्याय नहीं मिल पाया।

विशाखापट्टनम की यह त्रासदी कितनी भयानक है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि तीन से पांच किलोमीटर के क्षेत्र को खाली करा दिया गया यह हादसा इसलिए और भी घातक हो गया कि लोग रात में गहरी नींद में थे। जिसकी वजह से जहरीली गैस उनकी सांसो के ज़रिए फेफड़ों तक पहुंच गईं और लोगों की दम घुटने से मौत हो गयी। मीडिया में जो ख़बरें आई हैं उसके अनुसार कई मजदूर कम्पनी में थे। अगर ऐसा है तो उनकी भी मौत हो सकती है। शहर में लोगों के दरवाजे तोड़ कर पुलिस जांच कर रही है क्योंकि मरने वालों की संख्या अधिक हो सकती है। पांच किमी इलाके में लोगों को गैस रिसाव के चलते सांस लेने की दिक्कत हुई। इस दौरान पूरे देश में लॉकडाउन है। विशाखापट्नम ओरेंज जोन में है। जाहिर सी बात है कि अस्पताल पहले ही कोरोना युद्ध से लड़ रहे हैं। लोगों को सामाजिक दूरी बनानी होगी, उस स्थिति में इस तरह की समस्या अपने आप में बड़ी चुनौती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर गहरा दु:ख जताया। केंद्र सरकार पूरी घटना और राहत पर नज़र बनाए है। मुख्यमंत्री जगमोहन रेड्डी किंग जॉर्ज अस्पताल में पीड़ितों को देखने भी गए हैं। पूरे मामले पर खुद नज़र रखे हुए हैं और जिला में मौजूद सभी अधिकारियों को लोगों की जान बचाने के लिए तत्काल सभी संभव कदम उठाने को कहा है। लेकिन सबसे अहम सवाल है कि इस तरह की त्रासदी हुई कैसे ? निश्चित रुप से यह कम्पनी प्रबंधन की सबसे बड़ी लापरवाही है। क्योंकि कम्पनी लॉकडाउन से 40 दिन से बंद थी तो काम संचालन के पूर्व पूरे प्लांट की अच्छी तरह जांच और निगरानी क्यों नहीं की गई। रात के तीन बजे कम्पनी खोलने की क्या ज़रूरत थी। दिन में उसे क्यों नहीं खोला गया।

यह जिम्मेदारी उस स्थिति में और जवाबदेह बन जाती है जब प्लांट में इस तरह की ज़हरीली गैस का इस्तेमाल हो रहा हो। इसमें कोई दोराय नही कि कम्पनी प्रबंधन की तरफ़ से लापरवाही बरती गईं है। जब प्लांट बंद होने से पूर्व काम कर रहा था तो फिर लॉकडाउन के बाद कार्य चालू होने के बाद गैस का रिसाव कैसे हुआ। यह किसी तकनीकी गड़बड़ी से हुआ या किसी की साजिश से हुआ।प्लांट में चेतावनी का सायरन भी नहीं बजा इस मामले की गम्भीरता से पड़ताल होनी चाहिए। पुलिस ने स्थिति को देखते हुए सभी गांव वालों को सुरक्षित निकाल लिया है। लेकिन ज़हरीली गैस रिसाव के चलते लोगों के आंखों में जलन हो रही है। मासूम बच्चों और बुजुर्गों को स्वांस लेने में बड़ी दिक्कत हो रही है। यह परेशानी जानलेवा हो सकती है। यह प्लाण्ट एलजी पॉलिमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का है। 1961 में बना यह प्लांट हिंदुस्तान पॉलिमर्स का था। इसे 1997 में दक्षिण कोरियाई कंपनी एलजी ने अधिग्रहण कर लिया। आंध्रप्रदेश के उद्योग मंत्री गौतम रेड्डी ने यह माना है कि लॉकडाउन के बाद कम्पनी खोलते समय कहीं न कहीं चूक हुई है जिसकी वजह से गैस रिसाव की समस्या हुई है। सवाल उठता है कि केंद्र सरकार की तरफ़ से इस तरह के जोखिम भरी कम्पनियों के लिए सुरक्षा की गाइडलाइन ज़रूर जारी की गईं होगी। क्योंकि इस तरह के उद्योग रसायनिक प्रयोगों की वजह से जोखिम भरे होते हैं। यह जांच का विषय है कि 40 दिन बाद कम्पनी खोलने से पहले क्या सम्बन्धित गाइडलाइन का अनुपालन किया गया था या नहीं। अगर नही तो इसके लिए सीधे तौर पर कम्पनी प्रबंधन की जवाबदेही बनती है। जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि यह मसला लोगों की जिंदगी से जुड़ा है। विदेशी प्लांट भारत के लोगों की जिंदगी को इतना सस्ता क्योंकि समझते हैं। क्योंकि भोपाल और विशाखापट्नम की घटना विदेशी प्लांटों की वजह से हुई है। अपने आप में यह विचारणीय है।

राज्य और केंद्र सरकार की पहली प्रथमिकता है कि लोगों का जीवन बचाया जाय। प्रभावित परिवारों और लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाय। गैस के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए वैज्ञानिकों की मदद से प्रभावित इलाके को निष्प्रभावी बनाया जाय। इसका असर क्या हो सकता है लोगों को इसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जाय। इस गैस (स्टिरीन गैस) का प्रभाव क्या भोपाल गैस त्रासदी से भी गहरा है इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि भोपाल में 36 साल पूर्व हुई इसी तरह की घटना में हजारों बेगुनाहों ने अपनी जान गंवाई थी। भोपाल में भी रात्रि में गैस लीक हुई थी जिसकी वजह से गहरी नींद में सो रहे लोग सुबह नहीं उठ पाए थे। दमघुटने से उनकी मौत हो गई थी।

इस मामले में दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी- कड़ी से सजा होनी चाहिए। इस मामले में जाबबदेही तय होनी चाहिए। बेगुनाह लोगों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? क्योंकि अगर सच को जिंदा दफन किया गया तो भोपाल, विशाखापट्नम के बाद इसी तरह की और घटनाएं सामने आती रहेंगी और अनगिनत छोटी घटनाएं इस तरह की कम्पनियों में हो चुकी हैं।

इटली में भी गांव की ओर लौट रहे हैं लोग

कभी कोरोना से सबसे बुरी तरह प्रभावित रहे इटली में भी लोग अब गांवों की तरफ लौट रहे हैं। उनका कहना है कि इससे भविष्य में किसी भी महामारी या संक्रमण से निपटने में मदद मिलेगी। इनमें एक बड़ा तबका युवाओं का भी है। ज्यादातर युवाओं का कहना है कि वे शहरों में भाग- दौड़ भरी जिंदगी, हिंसा-आतंकवाद और नशे जैसी चीजों से छुटकारा चाहते हैं। अब गांवों में भी शहरों जैसी ज्यादातर सुविधाएं मौजूद हैं और इंटरनेट की वजह से ऑफिस के कई काम आसान हो गए हैं। ऐसे में उन पर शहरों में पड़ने वाला आर्थिक दबाव भी कम होगा।

इटली का संस्कृति मंत्रालय भी ग्रामीण इलाकों में पर्यटन, उद्योग और सुविधाएं बढ़ाने पर विचार कर रहा है। गांवों की तरफ लोगों का रुझान बढ़ने से सामाजिक-आर्थिक संगठन सरकार से ऐसी नीतियां बनाने की मांग कर रहे हैं, जिससे सूने हो चुके गांवों को आबाद किया जा सके। मिलान में कई इकोफ्रेंडली इमारतें बना चुके मशहूर आर्किटेक्ट स्टफिानो बोइरी कहते हैं, "यह साहसिक और व्यावहारिक फैसले लेने का वक्त हैं। अब शहरों को संक्रमण बम बनने से रोकना जरूरी है। महामारी ने लोगों के जीने का तरीका बदल दिया है। उन्हें पहाड़ी और ग्रामीण इलाकों में खाली पड़े गांवों में बसने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इटली में कम से कम 5800 गांव ऐसे हैं, जिनकी आबादी 5 हजार से भी कम है। करीब 2300 गांव ऐसे हैं, जहां कोई भी नहीं रहता। ऐसे में इन गांवों को गोद लेकर आबादी बसाई जा सकती है।

भारत में मरीजों की संख्या अभी और तेजी से बढेगी : गुलेरिया

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया का कहना है, सिर्फ आंकड़ों को देख पूरे देश का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अभी कर्व ग्राफ बढ़ रहा है। जबकि कुछ देशों में यह नीचे आ चुका है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार, कुछ देशों में वायरस का कर्व ग्राफ नीचे जा रहा है जिसमें अमेरिका भी शामिल है।

एक सप्ताह की स्थिति पर तैयार रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका, इटली, स्पेन, बेल्जियम और नीदरलैंड में कर्व नीचे की ओर आने लगा है। हालांकि ईरान, जर्मनी, ब्राजील, फ्रांस, यूके और भारत में अभी यह ऊपर की ओर है।डॉ. गुलेरिया बताते हैं, देश में डबलिंग व संक्रमण दर काफी हद तक नियंत्रण में दिखाई देगी। अभी रोजाना करीब 80 हजार जांच हो रही हैं। कुछ दिन में यह एक लाख से ज्यादा भी होंगी। तब हो सकता है कि रोज आ रहा आंकड़ा और भी ज्यादा हो।

लॉकडाउन में बाढ़ प्रबंधन पर भी ध्यान देना होगा

मुरलीधर

देश पहले ही एक महामारी से जूझ रहा है। अगर बाढ़ आई तो वह पिछले सालों के मुकाबले ज्यादा बड़ी चुनौतियां पेश करेगी। यह भी ध्यान में रखना जरूरी है कि बाढ़ नियंत्रण का काम इतना बड़ा है कि आने वाले दो महीने भी कम पड़ेंगे। ऐसे में बाढ़ की रोकथाम और उसके आने की स्थिति में राहत और बचाव के काम की तैयारी अभी से करने की दरकार है।

देश इस समय दोहरी आपदा से गुजर रहा है। आर्थिक मंदी से हम पहले से ही जूझ रहे थे। इस बीच कोरोना महामारी ने भी कहर बरपा दिया। इसका सीधा यह हुआ कि आर्थिक मंदी और बेरोजगारी की हालत और खराब हो गई। एक के बाद एक बढ़ते संकट के इस दौर में हमें यह भी सोच कर चलना चाहिए कि अब कोई नई विपदा और न आ जाए। मौसम के लिहाज से सोचें तो ऐसी ही एक संभावित आपदा है बाढ़। बाढ़ जैसा संकट कोरोना से निपटने के काम को और उलझा सकता है। पिछले कुछ साल से सामान्य बारिश के दिनों में ही जहां-तहां बाढ़ की तबाही मचने लगी है। मसलन, पिछले साल ही मौसम विभाग के सामान्य बारिश के अनुमान के बावजूद देश के तेरह राज्य बाढ़ की चपेट में आ गए थे। दस लाख से ज्यादा लोगों को घरों से भाग कर सुरक्षित जगह तलाशनी पड़ी थी। ऐसे में अगर हर साल जैसी बाढ इस बार भी हो गई तो मुश्किल हो जाएगी। विशेषज्ञों का अनुमान है कि अभी दो-तीन महीने तक कोरोना से बचाव के लिए सुरक्षित दूरी की जरूरत बनी रहेगी। उधर बाढ़ के अंदेशे का समय भी करीब दो महीने बाद आने को है। उस दौरान अगर बाढ़ के हालात बने और लोगों को घरों से निकाल कर कहीं एक साथ रखना पड़ा तो कोरोना से बचाव के लिए की जा रही सारी कवायद पर पानी फिर सकता है। इसलिए कोरोना के मददेनजर हमें अभी से बाढ़ प्रबंधन के काम पर लगने की जरूरत है।

भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून आमतौर पर एक जून को दाखिल होता है और पंद्रह जून तक पूरे देश में फैल जाता है, यानी हमारे पास कुछ करने के लिए बस एक-डेढ़ महीने का ही समय बचा है। देश जहां एक तरफ हर साल एक बड़ा भू-भाग पानी की किल्लत यानी सूखे से जूझता है, वहीं हर साल कई राज्य बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। यह भी हैरत की बात है कि जहां बाढ़ आती है, उन्ही इलाकों में कुछ महीने बाद पानी की किल्लत हो जाती है। एक ही साल में बाढ़ और सूखे की इस विसंगत स्थिति के लिए जल कुप्रबंधन से बेहतर और क्या शब्द हो सकता है? बहरहाल मौके पर याद करने की बात यह है कि कोरोना से बचाव में उलझे इस नाजुक वक्त में हम इस साल बाढ़ झेलने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में बाढ़ से बचाव की तैयारी को एक तरह से कोरोना के कहर से बचाव का ही काम समझा जाना चाहिए। देश में एक ही साल में बाढ़ और सूखे का सबसे बड़ा कारण यह है कि हम बारिश के पानी को रोक कर नहीं रख पाते। कुछ दशक पहले तक यह संकट इतना बड़ा नहीं दिखता था। उस दौर में जब तेज बारिश होने पर पानी नदियों को उफनाता हुआ वापस समुद्र में चला जाता था। तब नदियों के पाट भी खूब चौड़े थे। लेकिन बढ़ती आबादी ने बसावट के लिए नदियों से सट कर बस्तियां बसा लीं। इधर बढ़ी आबादी के लिए पानी की जरूरत भी बढ़ गई। लेकिन बारिश के पानी को गर्मियों के लिए सहेज कर रखने का प्रबंध उतना नहीं हुआ। जल विज्ञान के विशेषज्ञ हर साल बताते हैं कि हमें अपनी बढ़ती जरूरत के मुताबिक जल भंडारण क्षमता बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन ऐसा अब तक नहीं हो पाया है। इसीलिए काफी बड़े इलाके में पहले बाढ़ आती है और कुछ महीने बाद ही देश के ज्यादातर हिस्से सूखे का भी सामना करते हैं।

आखिर जल भंडारण क्षमता बढ़ाने में दिक्कत कहां है? इसे समझने के लिए देश में वर्षा जल उपलब्धता और जल भंडारण की वर्तमान स्थिति पर नजर डालना जरूरी है। भारत को प्रकृति से हर साल चार हजार अरब घनमीटर पानी मिलता है। लेकिन हमारी जल भंडारण क्षमता सिर्फ 257.8 अरब घनमीटर है, यानी हम मानसून के चार महीनों मे मिले कुल पानी का सिर्फ साढ़े छह फीसद हिस्सा ही अपने जलाशयों या दूसरी जल सरंचनाओं में जमा करके रख पाते हैं। हमारे पास पर्याप्त जल उपलब्ध है, पर संकट पैसे का है। अगर बहस कराई जाए तो बात केन-बेतवा नदी जोड़ परियोजना के जिक्र तक जाएगी और आखिर में निकल कर यही आएगा कि दिक्कत आर्थिक संसाधनों की ही है। इन नदी जोड़ परियोजनाओं के तहत कई श्रृंखलाबद्ध बांध बनने थे। हो सकता है कि पैसे की अड़चन अब तक वाजिब कारण रहा भी हो पर एक बार जरूर सोचा जाना चाहिए कि जल प्रबंधन का काम प्राथमिकता पर रखने से कितना कुछ हासिल हो सकता है।

शहरी इलाकों में जल निकासी को दुरुस्त करने के काम युद्धस्तर पर शुरू करने की जरूरत है। वरना कोरोना काल में लोगों को पानी के भराव वाले इलाकों से निकाल कर अगर राहत शिविरों में रखना पड़ा तो भारी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। र आपदा आने के पहले उसके प्रभाव को कम से कम रखने की तैयारी पहले से ही करनी पड़ती है। आपदा प्रबंधन के नियम यही कहते हैं।

हम कुल पानी का सिर्फ साढ़े छह फीसद हिस्सा ही अपने जलाशयों या दूसरी जल सरंचनाओं में जमा करके रख पाते हैं। केंद्रीय जल आयोग की साप्ताहिक रिपोर्ट के मुताबिक मई के पहले हफ्ते तक पिछले साल के मुकाबले हमारे जलाशय तिरसठ फीसद ज्यादा भरे हुए हैं और पिछले दस साल के औसत के हिसाब से भी ये जलाशय डेढ़ गुना ज्यादा भरे हुए हैं। जलाशयों में पहले से भरा पानी अगर महीने भर के भीतर खर्च न किया गया तो ऐन मौके पर बांधों को फौरन खाली करने की जरूरत पड़ सकती है। बाढ़ प्रबंधन के काम पर सिंचाई विभाग के इंजीनियरों को अभी से लगा दिया जाना चाहिए।

रेल हादसे की खबर व्यथित करने वाली

रांची : मुख्यमंत्री ने औरंगाबाद रेल हादसे पर दुख व्यक्त किया । मुख्यमंत्री ने कहा घटना मन को व्यथित करने वाली है। परमात्मा दिवंगत लोगों की आत्मा को शांति प्रदान करें। यह दुःखद है ! कोरोना और तालाबंदी का सबसे बुरा असर गरीबों पर पड़ा है, जो दिनों दिन इसे झेलने को मजबूर हो रहें हैं।

ब्रज गोपिका सेवा मिशन ने मुख्यमंत्री राहतकोष में दिये ढाई लाख रूपये

रांची :ब्रज गोपिका सेवा मिशन द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष में 2 लाख 50 हजार रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है । वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण उत्पन्न इस वैश्विक संकट में ब्रज गोपिका सेवा मिशन द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष में 2 लाख 50 हजार की सहायता राशि जमा कराई गई है। संस्था द्वारा बताया गया कि इस वैश्विक महामारी में वे अपने तरफ से जरूरतमंद लोगों तक हर संभव सहायता पहुंचा रहे हैं। साथ ही चैरिटी के माध्यम से चलने वाला यह संस्था वैश्विक महामारी में सरकार के साथ लोक हित के कार्यों में तत्परता से कार्य कर रही है।

सोचने समझने की क्षमता को प्रभावित करता है बढ़ता कार्बनडाइऑक्साइड

जर्नल जिओ हेल्थ में प्रकाशित एक नए शोध से पता चला है कि वातावरण में बढ़ता कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर हमारे सोचने समझने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ़ कोलोरेडो द्वारा किये गए इस अध्ययन से पता चला है कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। यह वृद्धि न केवल घरों के बाहर बल्कि अंदर भी हो रही है। शोध के अनुसार सदी के अंत तक घरों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर 1400 पीपीएम तक पहुंच जायेगा। जोकि वर्त्तमान में आउटडोर सीओ2 के स्तर से करीब तीन गुणा ज्यादा है। गौरतलब है कि हवाई के मौना लोआ ऑब्जर्वेटरी के आंकड़े के मुताबिक, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर 415.26 पार्ट्स पर मिलियन (पीपीएम) से ज्यादा हो चुका है। औद्योगिक क्रांति के बाद से इसके स्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। आईपीसीसी के अनुमान के अनुसार सदी के अंत तक वातावरण में सीओ2 का स्तर 930 पीपीएम हो जायेगा। जबकि शहरी इलाकों में बढ़कर 1030 पीपीएम तक पहुंच जायेगा। वातावरण में सीओ2 का यह स्तर हमारे सोचने समझने की क्षमता और निर्णय लेने की काबिलियत को प्रभावित कर सकता है।

सामान्य बुद्धिमता को 25 फीसदी तक कम कर सकती है, सीओ2 वैज्ञानिकों के अनुसार 1400 पीपीएम पर सीओ हमारी सामान्य बुद्धिमता को 25 फीसदी तक कम कर सकती है। जबकि जटिल निर्णय लेने की काबिलियत में करीब 50 फीसदी तक की कटौती कर सकती है। इस अध्ययन के प्रमुख शोधकर्ता क्रिस करनौस-ाकर ने बताया कि यह ने केवल बच्चों पर असर डालेगा, बल्कि एक आम इंसान, व्यापारी, वैज्ञानिक, शिक्षक, नीति निर्माता हर किसी पर इसका असर पड़ेगा।

ग्रामीण भारत पर टिकी आस

मुकेश रंजन

कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए शहरी भारत का एक बड़ा हिस्सा लॉकडाउन में है जबकि ग्रामीण भारत में कोरोनावायरस का असर अपेक्षाकृत कम हुआ है। इसके साथ ही रिकॉर्ड रबी की पैदावार हुई है। इससे सुधार का दारोमदार ग्रामीण भारत के कंधों पर टिका है। विश्लेषकों का कहना है कि ग्रामीण बाजारों से अपनी आय का बड़ा हिस्सा हासिल करने वाली कंपनियों को विशेष तौर पर इसका लाभ मिलेगा। गैर-लाभकारी ग्राहक शोध फर्म पीपल रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकनॉमी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्याधिकारी राजेश शुक्ला ने कहा, 'हमें उम्मीद है कि बीते समय की तुलना में ग्रामीण भारत में 1 से 2 फीसदी ज्यादा की वृद्धि हो सकती है।' उनका मानना है कि अच्छी फसल और ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने के सरकारी उपायों से वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा।

हालांकि केयर रेटिंग्स के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस का कहना है, 'ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेजी से विकास करने की प्रवृत्ति नहीं रही है और यह काफी कुछ इस पर निर्भर करेगा कि सरकार द्वारा उनकी किस फसल को किस दाम पर खरीदा जाएगा, साथ ही किसानों की आय और इलाके में विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र का भी अहम योगदान होगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि की हिस्सेदारी करीब 50 फीसदी है, शेष 50 फीसदी में छोटे एवं मझोले उपक्रमों के विनिर्माण और सेवाओं का योगदान होता है। इन फर्मों की किस्मत शहरी इलाकों में स्थित बड़ी कंपनियों से जुड़ी होती है। ऐसे में अगर शहरी अर्थव्यवस्था ठप रहती है तो ग्रामीण एसएमई भी प्रभावित होगी।

हालांकि वाहन, ट्रैक्टर और उपभोक्ता वस्तुओं से जुड़ी फर्मों का रुख आशावादी है। मजदूरों के वापस अपने गांव लौटने और अनुकूल मॉनसून के अनुमान से उन्हें खपत मांग बढ़ने की उम्मीद है। महिंद्रा एंड महिंद्रा में कार्यकारी निदेशक (कृषि एवं ऑटोमोटिव क्षेत्र) राजेश जेजुरिकर ने कहा, 'रबी की अच्छी पैदावार, क्रय केंद्रों के खुलने और फसल की अच्छी कीमत के संकेत, जलाशयों का स्तर आदि कई सकारात्मक कारक दिख रहे हैं, जो ग्रामीण भारत में वाहन एवं ट्रैक्टरों की मांग में सुधार का संकेत देते हैं। उन्होंने कहा कि क्रय केंद्रों के खुलने से ट्रैक्टरों की मांग बबढ़ेगी, वहीं अच्छी फसल से किसानों की आय बढने से महिंद्रा बोलेरो और स्कॉर्पियो और महिंद्रा पिकअप की भी मांग बढ़ेगी। मौजूदा हालात में देश की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र ही थोड़ी आस बांधती नजर आता है। केंद्र सरकार ने पिछले महीने कहा था कि कृषि क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद को 0 .5 से 1 फीसदी तक बढ़ा सकता है। नीति आयोग के सदस्य और कृषि अर्थशास्त्री रमेश चंद ने कहा कि कृषि क्षेत्र 3 फीसदी की वृद्धि दर्ज कर सकता है।डाबर इंडिया के मुख्य कार्याधिकारी मोहित मल्होत्रा ने कहा, 'जो लोग वापस अपने गांव आए हैं, वे जल्दी जाने वाले नहीं हैं। वे कम से कम मॉनसून सीजन तक गांव में ही रहेंगे और कृषि कार्य करेंगे। इससे खाने-पीने और रोजमर्रा की जरूरत की चीजों की मांग बढ़ेगी।

डाबर इंडिया की करीब 40 फीसदी बिक्री ग्रामीण इलाकों में होती है। कंपनी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से ग्रामीण इलाकों में टूथपेस्ट और च्यवनप्राश की बिक्री में सुधार देखा गया है।

अन्य को भी उम्मीद है कि शहरी भारत के लॉकडाउन रहने से ग्रामीण भारत अर्थव्यवस्था की गाड़ी को खींचेगा।पारले प्रोडक्ट्स में वरिष्ठद्द कैटेगरी प्रमुख मयंक शाह ने कहा, 'लॉकडाउन में रियायत मिलने से उत्पादन और अंतिम छोर तक वितरण में सुधार हो रहा है। प्रवासी मजदूरों के गांव लौटने की रफ्तार भी मई-जून तक थम जाएगी। जुलाई-सितंबर में ग्रामीण क्षेत्रों से मांग में सुधार होगा।'शाह ने कहा, 'सरकार लोगों के जनधन खाते में नकद पैसा डाल रही है, जिससे उनकी अतिरिक्त आय होगी।' पारले की बिक्री में 35 फीसदी योगदान ग्रामीण इलाकों का है। एस्कॉर्ट्स में सेल्स, मार्केटिंग और उभारते कारोबार के मुख्य कार्याधिकारी शेनू अग्रवाल का मानना है कि ग्रामीण-केंद्रित कंपनियों के लिए यह अच्छा मौका है। उन्होंने कहा, 'ग्रामीण मांग पूरी तरह से जरूरत आधारित होती है।' अग्रवाल ने कहा कि 20 से 30 अप्रैल के दौरान एस्कॉर्ट्स ने 1,000 ट्रैक्टरों की बिक्री की। और अब कंपनी की 70 फीसदी डीलरशिप पूरी तरह से खुल गए हैं।दोपहिया कंपनी हीरो मोटोकॉर्प को भी ग्रामीण इलाकों में मांग सुधरने की उम्मीद है। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा, 'हम अपने कार्यक्रम हर गांव, हर आंगन के जरिये ग्रामीण इलाकों में पहुंच रहे हैं और मांग का अनुमान लगाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही सर्विस हर जगह कार्यक्रम तथा आसान ऋण एवं लॉयल्टी लाभ के जरिये भी खरीदारों को आकर्षित कर रहे हैं।

.....पेज एक का शेष

रांची- नई दिल्ली राजधानी सुपर फास्ट स्पेशल ट्रेन सप्ताह में 2 दिन

- इन ट्रेनों के लिए स्टेशनों के काउंटर से रिजर्वेशन टिकट जारी नहीं किए जाएंगे
- इन ट्रेनों के लिए आईआरसीटीसी तथा रेलवे के अधिकृत एजेंट द्वारा टिकट रिजर्वेशन नहीं किए जा सकेंगे। यात्री स्वयं आईआरसीटीसी के वेबसाइट से टिकट बुक कर सकते हैं ।
- इन ट्रेनों में केवल कंफर्म आरक्षण प्राप्त किए यात्री ही यात्रा कर सकेंगे आरएसी तथा वेटिंग लिस्ट टिकट पर यात्रा की अनुमति नहीं रहेगी ।
- इन ट्रेनों के लिए करंट बुकिंग, तत्काल एवं प्रीमियम तत्काल बुकिंग लागू नहीं होंगे ।
- खानपान शुल्क इन टिकटों के भाड़े में समाविष्ट नहीं है, तथापि आईआरसीटीसी द्वारा सीमित खानपान एवं पीने के लिए पानी की व्यवस्था शुल्क के साथ उपलब्ध होगी ।
- स्टेशनों में सभी यात्रियों का स्क्रीनिंग अनिवार्य रूप से किया जाएगा तथा जिन यात्रियों में कोविड-19 के लक्षण नहीं पाए गए उन्हीं यात्रियों को ट्रेन पर चढ़ने की अनुमति दी जाएगी ।
- इन ट्रेनों में यात्रा करते समय प्रत्येक यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा तथा ट्रेनों में एवं स्टेशनों पर सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा।
- यात्रियों को गंतव्य स्टेशन पर उस राज्य के स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अनुसार नियमों का पालन करना होगा ।
- ट्रेन छूटने से 24 घंटे पहले ऑनलाइन ही टिकट रद्द किए जा सकेंगे टिकट कैंसिलेशन चार्ज 50% होगा ।
- सभी यात्रियों से अनुरोध है कि वह आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करें ।
- स्टेशन पर किसी भी प्रकार की खानपान की व्यवस्था नहीं रहेगी, कोई स्टॉल खुले नहीं रहेंगे ।यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वह कम से कम लगेज के साथ यात्रा करें।

फसलों में टीबी की दवा का इस्तेमाल बंद करें

रजिस्ट्रेशन कमेटी ने फसल के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन व टेट्रासाइक्लिन का इस्तेमाल 2022 के अंत तक बंद करने का सुझाव दिया है

एजेंसियां :सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी (केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति) के तहत रजिस्ट्रेशन कमेटी (आरसी) ने सिफारिश की है कि जहां जीवाणु (बैक्टेरियल) रोग नियंत्रण के लिए अन्य विकल्प मौजूद हो, वहां फसलों पर स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन जैसे एंटीबायोटिक्स का उपयोग तत्काल प्रभाव से और पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।अंतिम रिपोर्ट में स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट (9 प्रतिशत) और टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड (1 प्रतिशत) के उत्पादन, बिक्री और उपयोग पर उप-समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया है। आरसी की 414वीं बैठक 1 मई, 2020 को आयोजित हुई थी।रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि उन जगहों पर भी फसलों के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन का उपयोग 2022 के अंत तक बंद कर दिया जाए, जहां कोई विकल्प उपलब्ध नहीं थे। तब तक, फसलों के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल दवा का विवरण के अनुसार किया जा सकता है।6 मई, 2020 को इस बैठ का विवरण कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत, प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटाइन एंड स्टोरेज डायरेक्टोरेट की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था।नवंबर 2019 में विश्व एंटीबायोटिक जागरूकता सप्ताह के दौरान, सीएसई ने फसलों के लिए महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक दवाओं के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग को उजागर करते हुए एक विस्तृत मूल्यांकन रिपोर्ट जारी किया था।

मूल्यांकन रिपोर्ट में इस कुप्रथा को रोकने और इसे विनियमित करने के उपाय सुझाए गए थे। कृषि फार्मों में किए गए मूल्यांकन में, सीएसई ने पाया था कि किसानों द्वारा स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन का 90 :10 के अनुपात में, इसका हाई डोज नियमित रूप से फसलों पर इस्तेमाल किया जा रहा था।

मैत्री इंफ्रास्ट्रक्चर एंड माइनिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने राज्य सरकार को सहयोग किया

रांची :मुख्यमंत्री से कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में मैत्री इंफ्रास्ट्रक्चर एंड माइनिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन टी श्रीनिवास राव ने मिलकर कोरोना वायरस (कोविड-19) से निपटने हेतू एक लाख वासेबल एंड री-यूज मास्क राज्य सरकार को सहयोग किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण से उत्पन्न संकट की इस घड़ी में सभी लोग एकजुट होकर वैश्विक महामारी में आपसी सहयोग और सद्भाव से अपनी भूमिका निभाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने में स्वयंसेवी संस्थानों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। कोरोना वायरस की इस लड़ाई को हम सब मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। मौके पर मैत्री इंफ्रास्ट्रक्चर एंड माइनिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन श्री टी श्रीनिवास राव ने कोविड-19 संक्रमण से बचाव को लेकर राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। इस अवसर पर मैत्री इंफ्रास्ट्रक्चर एंड माइनिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रोजेक्ट मैनेजर श्री जी श्रीनिवास राव, प्रोजेक्ट मैनेजर जे सतीश एवं अन्य उपस्थित थे।

अन्नदाता किसानों के मनोबल बनाये रखने.....

....पेज एक का शेष

फ्रेंच बीन और खीरा की खेती से 5 हजार मात्र आमदनी हुई और करीब 50 हजार का अनुमानित नुकसान हुआ। देवरी गाँव के किसान सुनील कच्छप बताते है कि करीब 40 डेसीमल जमीन में धनिया और पालक साग की खेती में बारिश से नुकसान हुआ और बची सब्जी का बाजार एवं खरीददार नहीं होने से कोई आमदनी नहीं हुई। पूँजी की कमी के बावजूद अभी करीब 60 डिस्मिल जमीन में बोदी, अदरख और गरमा मकई की खेती शुरू की है। देवरी की महिला मुखिया मंजू कच्छप का कहना है कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों और कृषि विभाग के मार्गदर्शन में सब्जी फसलों की गुणवत्ता एवं उत्पादकता में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन बारिश व कोरोना ने किसानों की चिंता बढा दी है। क्षेत्र के किसान इन विपदा से आर्थिक रूप से कमजोर हो चले है। खेती के लिए किसानों के पास पूँजी नहीं रहा और परिवार की जीविका चलाना मुश्किल बनता जा रहा है। अन्नदाता किसानों के मनोबल को बनाये रखने पर पहल की जरूरत है।

डीन एग्रीकल्चर डॉ एमएस यादव कहते है कि करीब हर वर्ष आपदा को देखते हुए किसानों को बहु फसली खेती में खाद्यान, दलहनी एवं तेलहनी के साथ सब्जी फसलों की खेती करनी होगी. बहु स्तरीय खेती प्रणाली और एकीकृत कृषि प्रणाली को अपनाना होगा.किसान प्रत्येक फसल का फसल बीमा करायें। बाजार प्रबंधन को सुदृढ़ एवं प्रखंडो में कोल्ड स्टोरेज व प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना से किसान समस्याओं का हल संभव हो सकता है।

प्याज की अच्छी फसल पर लॉकडाउन की मार

राजन कुमार

देश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन लागू किया गया है। लेकिन इससे प्याज के किसानों को भयंकर नुकसान हुआ है। लॉकडाउन के कारण बाजारों तक पहुंच और मंडियों के बंद होने की वजह से प्याज के किसानों को फसल की लागत से भी कम पर प्याज बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

इस साल प्याज का उत्पादन अच्छा हुआ था, लेकिन मंडियों के बंद होने से किसान धीरे-धीरे गहरे वित्तीय संकट की ओर बढ़ रहे हैं। साथ ही खरीदारों की कमी और बेमौसम बारिश के कारण फसल के बर्बाद होने की संभावना भी बढ़ रही है।

सांवेर, महू, देपालपुर और इंदौर के किसानों ने दावा किया कि उन्होंने खरीददारों के न होने के चलते इस सप्ताह फसल की कीमत छह से सात रुपये प्रति किलो तय कर दी। किसानों ने बताया कि फसल की लागत ही आठ से नौ रुपये प्रति किलो है, लेकिन हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, इसलिए मजबूरन हमें इस कीमत पर फसल बेचने के लिए तैयार होना पड़ा। इंदौर जिले के कनाडिया गांव के रहने वाले एक किसान दिलीप मुकाती जिनके पास 500 बोरी (एक बोरी में 60 किलोग्राम) का स्टॉक है। उन्होंने बताया कि मैं अभी तक एक बोरी भी नहीं बेच पाया हूं। कुछ खरीददार खेतों पर आते हैं और मुझे सात से आठ रुपये प्रति किलो की कीमत देने को कहते हैं, जो कि लागत से बहुत ही कम है।मुकाती ने बताया कि किसानों के पास कोई चारा नहीं है, उनके पास दो ही रास्ते हैं, या तो वो जो कीमत मिल रही है उस पर अपनी फसल बेच दें। या फिर खुले आसमान में अपनी फसल को बर्बाद होते देखें।किसानों ने दावा किया लॉकडाउन के बीच इस क्षेत्र में बिचौलियों की बढ़ती मौजदूगी से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं, बिचौलियों को जमकर मुनाफा हुआ है। उन्होंने कहा, अधिकांश किसानों के पास खेतों में भंडारण की सुविधा का अभाव और पैसे की कमी है। जो उन्हें उत्पादन लागत से नीचे बेचने के लिए मजबूर कर रही है।

महू तहसील के एक अन्य किसान दिनेश पाटीदार ने कहा कि मेरे पास स्टॉक में प्याज की 2000 बोरियां हैं। न तो कोई परिवहन उपलब्ध है, और न ही व्यापारी हम तक पहुंच पा रहे हैं, ताकि हमें उचित मूल्य मिल सके। उन्होंने बताया कि पिछले साल उन्हें 30 रुपये से लेकर 40 रुपये प्रति किलो मिले थे। लेकिन इस साल उन्हें दो व्यापारियों द्वारा छह रुपये प्रति किलोग्राम की पेशकश की गई है। किसानों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि वह किसानों को सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचने में मदद करे, जिससे आपूर्ति श्रृंखला में बिचौलियों को हटाया जा सके। इंदौर नगर निगम (आईएमसी) विक्रेताओं के माध्यम से आलू और प्याज की शहर में आपूर्ति कर रहा है। साथ ही वह सब्जियों की भी आपूर्ति करने की योजना बना रहा है।

मैं स्वामी विवेकानन्द सरोवर बोल रहा हूँ....प्लीज मुझे बचाइए

विवेकानंदश्री

मैं स्वामी विवेकानंद सरोवर बोल रहा हूं. हां.. वही सरोवर जिसे आप बड़ा तालाब कहते हैं. जिसने पूरे रांची के जल स्रोतों को जिंदा रखा. जिसकी परिधि में बैठकर कई लोग फर्श से अर्श तक पहुंच गए. जिसके आसपास बैठकर और खेलकर कई पीढ़ियां जवान हो गई. जिस के पानी से आसपास के कई घर खड़े हो गए. वही बड़ा तालाब जिसने आपको सुकून भरी सांस दी. गर्मी में राहत पहुंचाई. जी हां...अभी कुछ दिन पहले मेरा नया नामकरण हुआ. मुझे देश के एक महापुरुष के नाम के साथ जोड़ दिया गया. स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने दुनिया में भारतीयता का डंका बजाया. तब मुझे भी बहुत गौरव हुआ था कि चलो मेरा भी नाम दुनिया जानेगी परंतु दुर्भाग्य कि मेरा नामकरण तो हुआ लेकिन काम कुछ नहीं हुआ. अब मुझे अफसोस लग रहा है कि क्यों मेरा नाम उस महापुरुष के साथ जोड़ दिया गया? क्यों मेरा नाम करण इतने बड़े महापुरुष के नाम पर किया गया? आज मुझे बहुत घुटन महसूस हो रही है. कोरोना के कारण आप सब को भी अपने अपने घरों में घुटन महसूस हो रही होगी और मुझे तो कई दशकों से घुटन महसूस हो रही है. अब ऐसा लग रहा है जैसे मैं वेंटीलेटर पर हूं. और अब न तब दम तोड़ दूंगा. कितने डॉक्टर आए, कितने विशेषज्ञ आए परंतु कोई भी मेरी समस्या का समाधान नहीं कर सके. पता नहीं मुझे स्वस्थ करने में कितने खर्च हो गए लेकिन उसका कोई लाभ मुझे नहीं मिला? अब घुट घुट के जी रहा हूं. ऐसा लगता है जैसे मेरी परिधि के आसपास रह कर जो लोग बड़े हुए उन्होंने मेरी परिधि को ही समेट दिया. आप मेरे पास आकर देखिए. मेरे दर्द को महसूस करिए. शायद आपको समझ में आए कि पहले तो मुझे मिलने वाले हवा पानी को रोका गया. गंदगी फेंकी गई. फिर भी किसी तरह में जीती रहा. सबका परोपकार करता रहा. सब की गंदगी अपने समाहित कर ली. इस उम्मीद में कि कोई आएगा और मेरी गंदगी को साफ करेगा लेकिन यह क्या? किसी ने ध्यान नहीं दिया. लोग मुझे समेटते गए, मेरी सीमाओं को बांध दिया. बाहर से मिलने वाले जल स्रोत बंद कर दिए गए और मैं घूंटता रहा.

मेरे ऊपर जलकुंभीयों ने अपना आश्रय बना लिया. किसी तरह मैं खुद को जिंदा रखा हूं परंतु अब ऐसा लग रहा है कि मैं जी नहीं पाऊंगा. 5 साल पहले मेरे सौंदर्य को निखारने की बात हुई. लोग कहते हैं करोड़ों रुपए खर्च हुए. स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा लगी. उस वक़्त मेरे आसपास आने वाले चर्चा करते थे कि अब इस तालाब का सौंदर्य निखरेगा परंतु यह क्या? इतने रुपए खर्च होने के बाद भी मेरा सौंदर्य नहीं निखर पाया. अब लोग मेरे आस-पास से गुजरते हैं तो नाक पर रूमाल रख लेते हैं. क्या मैं इतना बुरा हो गया हूं? मेरे चारों तरफ सीमेंट की मोटी मोटी दीवारें दे दी गई. लगातार मुझ में गंदगी फेंकी जाती रही. किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया. सौंदर्य निखारने के नाम पर लोगों ने मुझे तबाह कर दिया. अब तो सांस लेना भी दूभर हो रहा है. अब सोचता हूं तो लगता है कि मैं तो पहले ही ठीक था. जैसे भी था जी तो रहा था. लोग मुझसे नफरत तो नहीं करते थे आसपास बैठते तो थे. अब तो वह भी बंद हो गया.आइए, आज आपको अपना कुछ इतिहास बताऊं. 1840 के आसपास की बात है, तब इस देश में अंग्रेजी शासन था. अंग्रेजों ने मुझे बनाया था ताकि शहर के लोगों को पानी मिल सके. मेरे किनारे पर मंदिर भी बने. घाट भी बने. लोग पूजा करने आते थे. स्वास्थ्य लाभ लेने आते थे.

मेरे निर्माण के लगभग 100 साल बाद देश आजाद हुआ. मुझे लगा कि अब मुझे भी आजादी मिली है क्योंकि अंग्रेजी शासन में आखिर मुझे भी घुटन महसूस होती थी. फिर लगा कि आजाद हवा मुझे और निखारेगी परंतु किसी ने ध्यान नहीं दिया. इसके लंबे समय के बाद झारखंड अलग राज्य बना. तब फिर मुझमें और उम्मीद जागी. चलो अब मेरा कायाकल्प होगा. मुझे संरक्षण दिया जाएगा परंतु यह क्या? राज्य बने 20 साल हो गए. मुझे कुछ नहीं मिला. सिवाय गंदगी के. बावजूद इसके मैं सबका कल्याण करता रहा. आखिर यह भी कब तक कर पाऊंगा? अब मैं भी बूढ़ा हो चला हूं और मुझे भी इलाज की जरूरत है. कोई वैध, हकीम, डॉक्टर आए और मेरा इलाज करें. मैं आप सब से विनती कर रहा हूं कि मुझे बचा लीजिए. मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया. मेरा सब कुछ आपके लिए है. एक बार आइए मेरी गंदगी को निकालिए. मुझे अच्छी हवा दीजिए. मैं दोनों बाहें फैलाए आप सबके लिए हमेशा तैयार हूं. प्लीज बस एक बार मुझे साफ कर दीजिए।

फोटो न्यूज

छाया : उज्ज्वल

मानव निर्मित पहाड़: तस्वीर में रांची गोंदा जलाशय के किनारे रॉक गार्डेन की दोनों पहाड़िया नजर आ रही हैं पिछले साल से इन दोनों मनोरम पहाड़ियों के दृश्य के बीच अब एक मानव निर्मित पहाड़ (बड़ा बिल्डिंग) आकर दृश्य की सुंदरता बिगाड़ चुका है।

हल्दी :रसोई में मसालों की महारानी औषधी

ऋतु सिंह, योग प्रशिक्षक

हल्दी को मसालों की महारानी माना जाता है ।ये मसालों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। रसोई में तो इसका इस्तेमाल भरपूर है और इसके अलावा सेहत और सौन्दर्य का खज़ाना भी इसमें छुपा हुआ है ।हल्दी एंटी-ऑक्सीडेंट, एंटी-फंगल, एंटीसेप्टिक तत्व , विटामिन और मिनरल से भरपूर है ।हल्दी को गुणकारी औषधि के रूप में माना जाता है। हल्दी इतनी गुणकारी है कि इसकी व्याख्या जितनी करो उतनी कम है और तो और हर शुभ कार्य में हल्दी होती है जैसे, शादी-ब्याह,पुजा-पाठ आदि कार्यों में। शादियों में हल्दी की रस्म भी होती है और दुल्हन और दूल्हे को हल्दी का उबटन भी लगाते हैं जिससे उनका रंग-रूप निखरता है।

- हल्दी का सेवन मधुमेह को कम करता है और इसके जोखिम को भी कम करने में मदद करता है।
- कच्ची हल्दी मधुमेह रोगियों के लिए वरदान है। ये इन्सुलिन के स्तर को संतुलित रखता है।
- पाचन शक्ति को भी बढ़ने में ये काफी मददगार है। हल्दी के लगातार उपयोग से पाचन सम्बन्धी समस्या कम हो जाती है।
- हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर है, जिसके कारण यह रोग-प्रतिरोधक क्षमता के लिए उपयुक्त है।
- हल्दी में एंटी ऑक्सीडेंट गुण भी पाया जाता है,जो शरीर को फ्री रेडिकल्स से मुक्त रखने और आयरन के प्रभाव को संतुलित करने में सहायक होता है।
- इसके उपयोग से हड्डियों से जुड़ी समस्याओं में भी राहत मिलती है।
- कच्ची हल्दी में कैंसर से लड़ने में सहायक है ।यह खासतौर पर पुरुषों में होने वाले प्रोस्टेट कैंसर के कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकने के साथ-साथ उन्हें खत्म करने में भी मददगार है।
- इसके लगातार सेवन से कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है।
- हल्दी का लगातार इस्तेमाल लिवर को भी स्वस्थ रखता है।
- ये त्वचा को भी चमकदार और स्वस्थ बनाता है।
- धाव या किसी चोट पर हल्दी लगाने से जख्म बहुत जल्दी भरता है।

हल्दी का अन्य उपयोग कैसे करें

✓हल्दी वाला दूध सबसे आसान और काफी फायदेमंद होता है।

✓कच्ची हल्दी की सब्जी या अचार बनाकर खाना भी बहुत ही लाभकारी होता है।

✓हल्दी का पानी पीने के भी अपने फायदे होते हैं।

✓चेहरे पे थोड़ी सी हल्दी को मलाई ,बेसन,हनी आदि में मिला कर लगाने से त्वचा में निखार आता है।

✓बालों में हल्दी वाला पैक लगाने से बाल भी स्वस्थ और मजबूत बनते हैं।

✓हल्दी का लेप बनाकर किसी भी जख्म या कीड़े काटने वाले हिस्से में लगाने से काफी राहत मिलती है।

किसानों का पुराना दोस्त चमगादड़, अब शत्रु क्यों ?

देवाशीष

जब से ये बताया गया कि कोरोना वायरस चीन के वूहान में मांस के बाजार में चमगादड़ों से फैला तब से यह जीव एक दुष्ट खलनायक की तरह दिखने लगे हैं। हालांकि भारत में चमगादड़ों को अब तक नुकसानदेह नहीं माना गया है। जानकारी के अनुसार रोस्टस और पेट्रोपस प्रजाति के जिन चमगादड़ों के शरीर से निकला कोरोना वायरस दुनिया भर में कहर ढा रहा है, देश के विभिन्न इलाकों में इनकी तादाद लाखों में है। विशेषज्ञों का मानना है कि बेशक इन चमगादड़ों के शरीर में कई तरह के वायरस होते हैं लेकिन देश में ऐसी कोई मिसाल नहीं है जब उन्होंने इंसानों को कोई बड़ा नुकसान पहुंचाया हो। उल्टे फसलों में लगने वाले कीड़ों को खाकर वे सैकड़ों सालों से किसानों से दोस्ती निभाते आ रहे हैं।

रोस्टस यानी ओल्ड वर्ल्ड फ्रूट बैट यानी फल खाने वाला चमगादड़ पेड़ों की अधिकता वाले इलाकों में आसानी से देखे जा सकते हैं। कब्रिस्तान और श्मशान भूमि के पेड़ों पर भी सालों से इन चमगादड़ों का बसेरा है। अब तक इन चमगादड़ों का मनुष्यों पर कोई दुष्प्रभाव नहीं देखा गया है। दोनों प्रजातियों के चमगादड़ों में रोस्टस प्रजाति का चमगादड़ बहुतायत में हैं और पेट्रोपस यानी इंडियन फ्लाइंग फॉक्स प्रजाति के चमगादड़ अपेक्षाकृत काफी कम। रोस्टस को किसानों का सबसे अच्छे मित्र माना जाता है। रात के अंधेरे में पेड़ों से उतरकर वे खेतों में तमाम तरह के कीड़े खाकर उन्हें फसलों को नुकसान पहुंचाने से रोकते हैं। ये चील व कौओं की तरह मांसाहारी भी नहीं होते। फलों को खाकर जीवित रहते हैं। आम जैसी फसलों के सीजन में किसानों को नुकसान भी होता है मगर कुल मिलाकर इन्हें दुश्मन मानने के बजाय दोस्त के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। भारत में चमगादड़ नहीं खाए जाते इसलिएखतरा नहीं पर शोध हो जाए तो बेहतर आईएमए के पूर्व अध्यक्ष डॉ. रवीश अग्रवाल कहते हैं कि चीन में चमगादड़ों को खाए जाने की वजह से यह वायरस मनुष्य के शरीर में पहुंचकर संक्रमण की वजह बना लेकिन भारत में कुछ ट्राइबल इलाकों को छोड़ कहीं चमगादड़ नहीं खाए जाते हैं। ऐसे में इस चमगादड़ से भारत में कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका भी नहीं है। हालांकि अगर एहतियातन भ्रम दूर करने के लिए यहां पाए जाने वाले चमगादड़ों पर शोध करा लिया जाना बेहतर रहेगा।

झारखंड के बानो ईलाके में बड़े- बड़े फल खाने वाले चमगादड़ों की भरमार है साथ ही रांची के मोराबादी में युकलिप्टस और अकेसिया के ऊंचे पेड़ों की फुनगी पर सैकड़ो चमगादड़ उल्टे लटके दिखते हैं, पटना के गांधी मैदान में सुकून के लिये गर्मियों की शाम में बैठने वालों ने कतार में चमगादड़ों को गंगा की ओर जाते देखा होगा? ये चमगादड़ धुंधलका शुरू होते ही खाने की तलाश में उधर निकल पड़ते हैं। लेकिन इनसे किसी रोग के फैलने का एक भी उदाहरण नहीं है। उल्टे कीट पतंगों को खाकर ये किसानों के मददगार रहे हैं लेकिन चीन की करतूत से अब तक किसान मित्र रहा ये जीव अब किसी विलेन से कम नहीं दिखता।

चमगादड़ों के शरीर में हजारों सालों से है कोरोना वायरस

आईएमए उपाध्यक्ष डॉ. विनोद पागरानी का कहना है कि चमगादड़ों में कोरोना वायरस हजारों सालों से है मगर कभी मनुष्यों में ट्रांसफार्म नहीं हुआ। आईसीएमआर की कहती है कि करीब एक हजार सालों में एक बार ही ऐसा होने की आशंका है।

विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020

नंद किशोर कानवन

09 मई का दिन पूरे विश्व में "विश्व प्रवासी पक्षी दिवस" के रूप में मनाया जाता है। वैश्विक स्तर पर करीब 2000 पक्षियों की प्रजातियां भोजन एवं प्रजनन के लिए हर साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करती हैं। ये प्रवासी पक्षी कुछ 100 किमी से लेकर 14000 किमी तक का सफर करते हैं।

भारत में आर्कटिक, साइबेरिया, यूरोप एवं अफ्रीका जैसे सूदूर प्रदेशों से छोटी बड़ी तकरीबन 370 प्रजातियां प्रवास करती हैं। इस के अलावा 200 से अधिक भारतीय प्रजातियां स्थानीय प्रवास करती हैं। अधिकतर गतिविधियां सर्दियों के मौसम में होती हैं और इनमें ज्यादातर पानी के पक्षी और शिकारी पक्षी होते हैं।
बहुत दुःख की बात है कि पिछले कुछ सालों में इन प्रवासी पक्षियों की संख्या में खतरनाक गिरावट आई है। अंदाजन 40% प्रजातियों की संख्या में 20 % की कमी दर्ज की गई है। 200 प्रजातियां लुप्तप्राय की श्रेणी में पहुंच गई हैं ।इस गंभीर गिरावट के मुख्य कारण हैं-

- आर्द्र भूमि , घास के मैदानों और जंगलों का अवैध कटाई एवं कब्जों द्वारा सिकुड़ना।
- बड़े पैमाने पर अवैध शिकार।
- ही३ʼल्ल२ में मछली पालन और जालों का लगाना।
- खतरनाक स्तर का जल एवं वायु प्रदूषण
- . पनचक्की, बिजली के ऊंचे खम्बे, ऊंची इमारतें और बिजली की चकाचौंध।

आइए आज अभी से यह प्रण लें कि जितना हो सके, अपने अपने कार्य क्षेत्र में प्रकृति की इस अनमोल रचना को बचाएं और अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करें।

लद्दाख में फंसे झारखंडी मजदूर

आनंद दत्त

लद्दाख, करगिल में झारखंड के 150 से अधिक मजदूर फंसे हुए हैं। ये अपने घर आना चाहते हैं, लेकिन अब तक राज्य सरकार ने कोई ठोस इंतजाम नहीं किया है। लद्दाख के गोरगोदोह इलाके में मजदूरी कर रहे पूरन देहरी ने बताया कि वह दुमका के रहनेवाले हैं। पहाड़िया आदिवासी हैं। लद्दाख आए नौ महीने हो चुके हैं। घर लौटने का समय आया तो लॉकडाउन हो गया। वे लोग सड़क निर्माण का काम करते हैं। उन्हें ठेकेदार लेकर आया था, लेकिन निर्माण का काम भी दो महीने से बंद है।

वहीं रामेश्वर देहरी ने बताया कि प्रत्येक मजदूर का ठेकेदार पर लगभग 55,000 रुपया बकाया है, जो उन्हें मिलना है। सड़क निर्माण कंपनी की तरफ से ये पैसा ठेकेदार को दिया जा चुका है, लेकिन ठेकेदार चला गया है। उसी के पास इन लोगों के कागजात और एटीएम हैं। यही वजह है कि उनके पास पैसा भी नहीं है। लिचु पहाड़िया ने बताया कि आसपास के लोगों की मदद से खाना खा रहे हैं। उसमें भी केवल रोटी और चावल खा पाते हैं। सब्जी खाए तो कई दिन हो गए। चामरु देहरी ने बताया कि गांव में खेती-बाड़ी का समय हो गया है। परिजन इंतजार कर रहे हैं। वहां भी परेशानी है, वह हाट-बजार भी नहीं जा पा रहे हैं, जिस वजह से घर में भी पैसा नहीं आ पा रहा है ।सोनातोम देहरी के मुताबिक झारखंड के लोग करगिल और लद्दाख के अलावा थरूस, दरचिग, गोरगोदो जैसे इलाकों में भी हैं। सभी सड़क निर्माण का ही काम करते हैं। लेह के इलाके में तो तीन दिन की चढ़ाई कर वहां पहुंचते हैं, फिर काम करते हैं। करगिल में काम कर रहे शिबू ने बताया कि वह घर जाना चाहते हैं, लेकिन कोई उपाय नहीं दिख रहा है।

हालांकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार ये कहते रहे हैं कि मजदूर जब तक आना चाहें, सरकार उन्हें लाती रहेगी। चाहे इसके लिए हवाई जहाज का ही इस्तेमाल क्यों न करना पड़े। लद्दाख, करगिल से सीधे रेलमार्ग और मजदूरों की संख्या कम होने से हवाई मार्ग से ही इन्हें लाना संभव है. एक ट्वीट कर उन्होंने इन मजदूरों के लिए लद्दाख गवर्नर ऑफिस और लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल से मदद की अपील की है। हालांकि मजदूरों के वापस आने की संभावनाओं पर कोई बयान नहीं दिया गया है।

किसान पशुओं को खिला रहे ब्रोकली

एजेंसियां

वैश्विक महामारी कोरोना के चलते यूरोपियन फसल ब्रोकली का कारोबार ठंडे बस्ते में है। जिससे किसानों को लाखों रुपये की क्षति झेलनी पड़ रही है। होटल व्यवसाय बंद होने से खेतों में ही सड़ रही है। महामारी के कारण जिला भर के किसानों को रोजी रोटी के लाले पड़ गए हैं। जिला सोलन में सबसे अधिक यूरोपियन फसलों की पैदावार चायल क्षेत्र में की जाती है। यही नहीं विभाग के पास अभी तक 35 से 40 किसानों ने समस्या को बताया है। जिसके बाद विभागीय अधिकारियों ने क्षेत्र में क्षेत्रफल के हिसाब से रिपोर्ट को तैयार किया है। जानकारी के अनुसार सोलन में शमलेच, चायल, झाजा, नगाली, हिन्नर, सकोड़ी, बांजनी में यूरोपियन फसलों को अधिक मात्रा में लगाया जाता है।

किसान और उपप्रधान झाजा सुरेंद्र कुमार ने बताया कि वह 20 सालों से फसलों को लगाने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 50 बीघा में लगी फसल को 30 से 35 लाख रुपये का नुकसान हो चुका है। जिसके कारण उन्हें अपनी उपज को पशुओं को ही खिलानी पड़ रही है या फिर फेंकने को मजबूर हो रहे हैं। मनीष कुमार, श्याम दत्त, पवन कुमार, अजय कुमार ने बताया कि यूरोपीयन फसलों को कारोबार होटल और रेस्टोरेंट बंद होने के कारण तबाह हो चुका है। बताया कि सोलन मंडी में उपनी उपज को लेकर गए थे। लेकिन 3 से 5 रूपये किलों ही ब्रोकली की खरीद हुई। जिससे किसानों को हानि हुई है ।उप-निदेशक कृषि विभाग पीसी सैनी से बताया कि यूरोपियन फसल ब्रोकली की ज्यादातर मांग बड़े होटलों में रहती है। उन्होंने बताया कि किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान चायल क्षेत्र सहित आसपास हुआ है। इसकी रिपोर्ट क्षेत्र के हिसाब से तैयार की गई थी। उन्होंने बताया कि किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता के तौर पर लेकर कार्य जारी है।

हम प्रकृति को उसके हाल पर छोड़ दें

स्वरांगी साने

सुबह उठते ही आप परदा हटा कर खिड़की से बाहर देखते हैं। शाम ढले भी आपका मन परदे सरका कर बाहर देखने का होता है। वह खिड़की होती है। भले ही वह दफ्तर की खिड़की हो या आपके घर कीङ्क रोज-ब-रोज आप बाहर क्या देखना चाहते हैं? उस तयशुदा खिड़की के बाहर वही सब तो होता है, उसी तरह तयशुदा! मसलन, वही पेड़ जिसे कल भी देखा था, वही इमारत, उस इमारत से सटी कोई और दूसरी इमारत, कोई और दूसरा पेड़, आकाश का वह छोटा-सा टुकड़ा! लेकिन हर बार आप बाहर देख कर आनंदित, तरोताजा महसूस करते हैं। ऐसा क्यों?

दरअसल, प्रकृति परिवर्तनशील है। कल जो दिखा, उससे आज कुछ अलग दिखता है। वही पेड़ होगा, लेकिन उसकी पत्तियां कल कुछ कम हरी, आज अधिक हरी नजर आती हैं या कभी वे पीली पड़ती दिखती हैं। सामने वाली इमारत की किसी दूसरी खिड़की में कुछ और बदलाव नजर आता है और आसमान का रंग! वह तो हर पल छटा बदलता है। बादलों के टुकड़े उड़ते चले जाते हैं, पेड़ के पत्ते लहलहाते हैं और बाहर से आने वाली रोजमर्रा की आवाजें भी हर दिन कुछ अलग होती हैं, भले ही वे उसी क्रम में क्यों न सुनाई पड़ें! मनुष्य को परिवर्तन इतना अधिक प्रिय है कि वह हर चीज में परिवर्तन चाहता है। जो परिवर्तनशील नहीं, वह हमारी प्रकृति का हिस्सा नहीं होता। सौंदर्य की परिभाषा देते हुए महाकवि कालिदास कहते हैं कि प्रतिक्षण बदलने की प्रवृत्ति ही सौंदर्य है। शायद फैशन की भी यही परिभाषा है। हम लगातार कुछ नया चाहते हैं, इसलिए जो गतिमान नहीं है, उसके प्रति हमारे मन में सहज कौतूहल तो होता है, लेकिन कुछ समय बाद हम उकता जाते हैं और हमारे मन में बदलाव की इच्छा प्रबल होने लगती है। हर पल नया देखने-सुनने, पाने की चाह ही चौबीस घंटे की 'ब्रेकिंग न्यूज' को प्रबल बनाती है। यही चाहना तो हमारे पास जो नई जानकारी आती है, उसे तुरंत आगे बढ़ाने, अग्रेषित करने का मोह जगाती है। हम चाहते हैं कि दुनिया जाने कि हर जानकारी सबसे पहले हमारे पास है।

आप जिस घर में रहते हैं, उसे बदलना चाहते हैं। या तो उससे बड़ा घर चाहिए होता है या वह मोहल्ला और कई बार तो वह शहर ही बदल देना चाहते हैं। और तो और, देश भी। आज जो फ्रिज है, कल वह पुराना लगने लगता है। फिर वाशिंग मशीन, एसी, टीवी, लैपटॉप-मोबाइल, जूते-कपड़े, बदलते चले जाने की लालसा खत्म नहीं होती।

कभी हम प्रकृति को उसके हाल पर क्यों नहीं छोड़ देते? जब बदलाव आवश्यक होगा तो बदलाव होगा, यह तटस्थ भाव हममें क्यों नहीं जग पाता? हमारी पीढ़ी ने अपने से पहले की पीढ़ी को देखा है, जिसके पास सब कुछ सीमित था। सीमित वस्त्र-अलंकार थे, बहुत सीमित में उनका गुजारा हो जाता था। पुश्तैनी मकान उस जमाने की खासियत थी। मतलब वह मकान जिसमें उनके भी पुरखों के पुरखे रहते चले आए थे, और किसी ने बदलाव नहीं चाहा था। अब हमें ऐसा क्यों नहीं लगता कि हमें परिवर्तनशील से अपरिवर्तनशील की ओर चलना चाहिए। चलायमान से ठोस, स्थिर बातों पर जोर देना चाहिए। अगर हमारा ध्यान अपने ठोस स्वरूप की ओर केंद्रित होगा, तभी हमारी अपने से पहचान होगी। गीता का श्लोक कहता है न कि आत्मा पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करती है। पर हम तो रोज नए वस्त्र धारण करते हुए भूल जाते हैं कि हममें जो आत्मा बसी है, वह हमारा सच्चा स्वरूप है।

वे लोग जिन्हें हमने देखा है, उनसे नई पीढ़ी का परिचय कैसे होगा, तो वे हमारे आचरण से उन तक पहुंचेंगे। कुछ कपड़ों में भी जीवन जीया जा सकता है। हर शादी-ब्याह, वार-त्योहार, पार्टी-उत्सव के लिए अलग-अलग कपड़ों की जरूरत नहीं है। उन लोगों के पास भारी कपड़ों के नाम पर संदूक में रखे कुछ अलहदा कपड़े होते थे और हर बड़े कार्यक्रम में उन्हें ही पहना जाता था। उस दौर के सब लोग ऐसा ही करते थे तो कोई 'शो-ऑफ' यानी दिखावा नहीं था। दिखावा नहीं था, तो झूठी आन-बान-शान में जीने का चलन भी नहीं था। सादगी से रहते थे तो अधिक ठोस बातों की ओर ध्यान देने का समय मिल जाता था। हर बार नए कपड़े, नई वस्तु खरीदने के लिए बाजार जाने की जरूरत नहीं थी। बाजार जाना महीने में एक बार होता था, न कि हर हफ्ते के आखिर में, तो भला बाजारवाद कैसे हावी हो पाता? आइए, दिखावे को दरकिनार करते हैं। हर दौर में निश्चित ही समस्याएं भी थीं और संघर्ष भी, लेकिन उनका स्वरूप और उनका विस्तार कितना था, यह भी सोचा जाना चाहिए और तब जन आकांक्षा व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा से अधिक बढ़ कर सामाजिक चेतना की थी, इसे भुलाया नहीं जा सकता

E ZONE CARE

Software Problem, Motherboard Chip-Level Repair, Laptop AC Adapter Repair and Replacement, Laptop LCD Screens Repair and Replacement, Dead Laptop Problems, No Display Problem, LCD Dim Display Problem, LCD White Display Problem, BIOS Password Problem, all type of Laptop repair and service

• Repair your laptop with 3-month warranty.

info@ezonecare.in, ezonecare.in
Rospa Tower 3RD Floor, Main Road, Ranchi 93108 96575, 70047 69511
Mon - Fri 10:30 am - 7:00 pm
SUNDAY CLOSED

अखबार के स्वामी सन कम्युनिकेशन के लिये प्रकाशक मनोरंजन सिंह द्वारा प्रकाशित तथा मेसर्स डी. बी. कॉर्प लिमिटेड,प्लॉट नं535 एवं 1272 ललगुटवा पुलिस स्टेशन, रातू, रांची (झारखंड) से मुद्रित और सन कम्युनिकेशन,अपोजिट कब्रिस्तान गेट नं.-2, टीवीएस गली, रातू रोड, रांची-834001 (झारखंड) से प्रकाशित। संपादकः एम.के.शर्मा * (पी.आर.बी. अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिये उत्तरदायी)आर.एन.आइ. पंजीयन क्रमांक : JHAHIN/2019/78094, email:greenrevolt2019@gmail.com.☎ 0651-2283018, 8539978825, 8825374626. समस्त विवाद रांची न्यायालय के अधीन होंगे।